नई सोच • नई शुरूआत • नया भारत

अनप्लग इंडिया

सच की आवाज, भारत की पहचान

नोएडा एनसीआर संस्करण

वर्ष : 01 | अंक : 36 | नोएडा, वीरवार, 5 नवम्बर, 2026 | Website: www.unplugindia.com | पृष्ठ : 8 | मूल्य : 03 रुपए

आज का विचार

‘आँख खुलते ही शुक्रिया कहो, क्योंकि आज फिर से कोशिश करने का मौका मिला है। ‘





अग्निवीरों को मोदी सरकार का दीवाली गिफ्ट!

● पचहत्तर फीसदी को मिलेगा 2 साल का एक्सटेंशन ● सीडीएस का ऐलान-सैलरी भी बढ़ेगी, नौकरी पक्की

नई दिल्ली (एजेंसी)। नरेंद्र मोदी सरकार ने अग्निवीरों को बड़ा दीवाली गिफ्ट दिया है। केंद्र ने अग्निवीरों की सेवा अवधि बढ़ाने का ऐलान किया है। सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने बताया कि अग्निवीरों को दो साल का और इंगेजमेंट पीरियड मिलेगा। इसके बाद आर्म्ड फोर्सेज में भी एनरोलमेंट किया जाएगा। दो साल का पीरियड पूरा होने के बाद ऑब्जेक्टिव सेलेक्शन प्रक्रिया के जरिए उन्हें सेना में भर्ती का मौका मिलेगा। सरकार ने बुधवार को ‘अग्निवीरों’ को दो साल का सेवा विस्तार देने की घोषणा की। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब करीब 18,000 अग्निवीरों को कुछ सप्ताह बाद सशस्त्र बलों से सेवामुक्त होना था। सीडीएस जनरल एन एस राजा सुब्रमणि ने कहा कि सभी अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में अपनी सेवा जारी रखने का अवसर दिया जाएगा।



अग्निवीरों को मिलेगा सेवा विस्तार

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा कि आज का दिन भारतीय रक्षा बलों और हमारे अग्निवीरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैबिनेट ने सभी अग्निवीरों के लिए भारतीय रक्षा बलों में शामिल होने का रास्ता खोल दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को शुरू की गई थी। उस समय यह बताया गया था कि अग्निवीरों के प्रदर्शन का लगातार मूल्यांकन किया जाएगा और समय-समय पर इस योजना की समीक्षा की जाएगी। सीडीएस ने कहा कि अग्निवीरों का पहला बैच अब अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करने के करीब है। इन चार वर्षों में किए गए प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर, हमें उनके काम को लेकर बहुत सकारात्मक फीडबैक मिला है।

डिफेंस फोर्सेज में नियमित सेवा का भी मौका

सीडीएस ने कहा कि कैबिनेट ने सभी अग्निवीरों के लिए रास्ता बनाया है ताकि वे डिफेंस फोर्स में अब्जॉर्बर हो जाएं। मेरिट के हिसाब से 25 पर्सेंट को रेगुलर सैनिक बनाया जाएगा। बाकी 75 पर्सेंट को 2 साल का इंगेजमेंट पीरियड का ऑफर दिया जाएगा। इस तरह से 75 फीसदी अग्निवीरों को 2 साल एक्सटेंशन-सैलरी भी बढ़ेगी, नौकरी पक्की करने का मौका होगा।

75 फीसदी अग्निवीरों को दो साल का एक्सटेंशन

उन्होंने कहा कि पहले 75 फीसदी अग्निवीरों के लिए यह प्रावधान था कि वे अनुशासित और प्रेरित युवाओं के रूप में वापस समाज में लौट जाएंगे। हालांकि, इस अपडेट की गई योजना के तहत, बाकी बचे 75 फीसदी अग्निवीरों को अब दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल दिया जाएगा।

संक्षिप्त समाचार

सीईसी ज्ञानेश पर 20 साल पुराने आरोप की होगी जांच

● केरलम में 2 करोड़ रुपए रिश्वत मांगने का लगा था आरोप

तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 20 साल पुराने रिश्वत मांगने के आरोपों की जांच होगी। केरलम के गृहमंत्री मेश चेन्निथला ने विजिलेंस को जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला सड़क निर्माण प्रोजेक्ट से जुड़ा है। उस समय ज्ञानेश कुमार राज्य में पीडब्ल्यूडी सचिव थे। कोल्लम के ठेकेदार साजन का आरोप है कि ज्ञानेश कुमार ने केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का काम पूरा होने के बाद पेमेंट करने के बदले 2 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। इस समय कांग्रेस की अगुवाई में पूरे देश में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एसआईआर में गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी साल मई में हुए विधानसभा चुनाव में केरलम में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ ने 140 में से 97 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। कांग्रेस ने यहां 10 साल बाद सत्ता में वापसी की है। साजन के मुताबिक, इंजीनियरों ने करीब 17 करोड़ के बिल मंजूर कर दिए थे, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने चेक रोक दिए। इससे मलेशियाई कंपनी उसके ठेकेदारों और कर्मचारियों को आर्थिक परेशानी हुई। कंपनी के प्रोजेक्ट इंजीनियर ली सी बीन ने उन्हें (साजन को) बताया था कि ज्ञानेश कुमार रिश्वत मांगे बिना भुगतान के चेक जारी नहीं कर रहे हैं।



लोकतंत्र में धरना और भूख हड़ताल की जगह नहीं

● हाईकोर्ट बोला-यूनिवर्सिटी राजनीति नहीं, पढ़ाई की जगह

तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि धरना, भूख हड़ताल और सत्याग्रह जैसी गतिविधियों की संवैधानिक लोकतंत्र में जगह नहीं है। कोर्ट ने कहा- शिक्षण संस्थान पढ़ाई के लिए हैं, राजनीति के लिए नहीं। ऐसी गतिविधियों में शामिल छात्रों को संस्थान से निष्कासित किया जा सकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी कालडी स्थित श्री शंकराचार्य संस्कृत



यूनिवर्सिटी के 16 निलंबित छात्रों के मामले में की। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के उस अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें छात्रों को 4 नवंबर से शुरू होने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं में बैठने की इजाजत दी गई थी। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब 16 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े इन छात्रों ने परीक्षा में बैठने की इजाजत देने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे उनका पूरा सेमेस्टर बर्बाद हो सकता है। यूनिवर्सिटी में 13 अगस्त को सिंडिकेट की बैठक के दौरान लेफ्ट से जुड़े छात्रों ने प्रदर्शन किया था। वे कैंपस में बुनियादी सुविधाओं की कमी, पानी की समस्या और शिक्षकों के खाली पद भरने जैसी 18 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे।

होसबाले बोले-हमने पूरा किया आरएसएस का संकल्प

हमें राम मंदिर बनाकर दिखाना था, वह हमने बना दिया: संघ

इंदौर में सरकार्यवाह ने कहा-आरक्षण को लेकर न हो राजनीति



इंदौर (एजेंसी)। इंदौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक बुधवार को समाप्त हो गई। डेली कॉलेज में 2 नवंबर से चल रही इस बैठक में देशभर से करीब 400 प्रतिनिधि शामिल हुए। समापन के बाद सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने आरक्षण, मंदिरों के मामलों, संगठन विस्तार, एसआईआर, संघ के पंजीयन और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर संघ का पक्ष रखा। आरक्षण पर होसबाले ने कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को जब तक समान अवसर नहीं मिलते, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। इसका लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुंचना चाहिए। कृष्ण जन्मभूमि समेत अदालतों में चल रहे मंदिरों के मामलों पर उन्होंने कहा, ‘हमें राम मंदिर बनाकर दिखाना था, वह हमने बना दिया।

एक साल में 10,241 नए स्थानों तक पहुंचा संघ

होसबाले ने बताया कि संघ के शताब्दी वर्ष में संगठन का विस्तार हुआ है। एक साल में संघ की पहुंच 10,241 नए स्थानों तक बढ़ी है। अब देश के 63,208 स्थानों पर 99,423 शाखाएं संचालित हो रही हैं।

मोबाइल से दूर रखने के बजाय बच्चों को संस्कार दें

नए जनसंचार माध्यमों और मोबाइल के इस्तेमाल पर होसबाले ने कहा कि तकनीक को रोकना आसान नहीं है। बच्चों को इंटरनेट और मोबाइल से पूरी तरह दूर रखने के बजाय उन्हें सही संस्कार देना जरूरी है। स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संस्थाओं की इसमें अहम भूमिका है। माता-पिता को तय करना चाहिए कि बच्चों को किस उम्र में डिवाइस देना है और वे कितनी देर उसका इस्तेमाल करें। उन्होंने परिवारों से अपील की कि दिन में या सप्ताह में आधा से एक घंटा मोबाइल से दूर रहकर सभी सदस्य साथ बैठें और सकारात्मक विषयों पर बातचीत करें। मंदिर जाने वाले लोग बच्चों को भी साथ ले जाएं और उन्हें धार्मिक-सामाजिक परंपराओं का महत्व समझाएं।

बंगाल में 150 गुना बढ़ीं शाखाएं, केरल के हर गांव तक पहुंचने का दावा

संघ की शाखाओं के विस्तार पर होसबाले ने कहा कि पश्चिम बंगाल में शाखाओं की संख्या पहले की तुलना में 150 गुना बढ़ी है। पहले वहां शाखाएं लगाने का विरोध होता था। त्रिपुरा और असम में संघ के कई कार्यकर्ताओं की हत्या भी हुई, लेकिन संगठन का काम जारी रहा। मिजोरम में दो जगह और लद्दाख में भी शाखाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने दावा किया कि केरल के सभी गांवों में संघ की शाखाएं हैं। होसबाले ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए संघ विशेष योजना बनाएगा।

अमेरिका में मिडटर्म चुनाव हारे राष्ट्रपति ट्रंप

● दोनों सदनों में करारी हार, डेमोक्रेट्स को बहुमत ● पहले मुस्लिम सीनेटर बनेंगे अब्दुल अल-सैयद ● चुनाव प्रचार में ट्रम्प ने उन्हें ‘जिहादी’ कहा था

वाशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी को हार मिली है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों सदनों में बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं, मिशिगन में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अब्दुल अल सैयद ने जीत हासिल की। इसके साथ ही वह अमेरिकी इतिहास में सीनेटर चुने जाने वाले पहले मुस्लिम बन गए हैं। ट्रम्प ने अब्दुल को खुले मंच से जिहादी कहा था। 25 अक्टूबर को मिशिगन में एक चुनावी रैली के दौरान ट्रम्प ने कहा था,मैं यहां एक जिहादी और मुस्लिम ब्रदरहुड के सदस्य को अमेरिकी सीनेटर बनने से रोकने आया हूं।



हार के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल

अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को मिली हार के बाद बाजार में यह अनिश्चितता बढ़ी है कि ट्रम्प ईरान युद्ध को लेकर आगे क्या फैसला लेंगे। इसी चिंता का असर कच्चे तेल की कीमतों पर दिख रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक, बुधवार सुबह ब्रेंट क्रूड की कीमत 76 सेंट यानी 0.7 फीसदी बढ़कर 104.36 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई।

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, सीनेट सब हारे

हाउस में कुल 435 सीटें हैं और सभी सीटों पर चुनाव हुए हैं। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने 231 सीटें जबकि ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी ने 144 सीटें जीती हैं। सीनेट की 100 सीटों में से 35 पर चुनाव हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 33 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। इनमें डेमोक्रेटिक पार्टी ने 20 और रिपब्लिकन पार्टी ने 13 सीटें जीती हैं। बाकी 2 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। इन नतीजों को मिलाकर डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 54 और रिपब्लिकन पार्टी के पास 44 सीटें हैं।

राजस्थान में रेलवे ट्रैक पर जबरदस्त ब्लास्ट

45 मिनट पहले पैसेंजर ट्रेन गुजरी थी, बाल-बाल बची



अनूपगढ़ (एजेंसी)। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में रेलवे लाइन पर मंगलवार रात 9.45 बजे ब्लास्ट हो गया। अनूपगढ़-सूरतगढ़ ट्रैक पर धमाके से पहले रात 9 बजे पैसेंजर ट्रेन गुजरी थी। धमाके की आवाज 200 मीटर दूर तक सुनाई दी। ब्लास्ट के कारण पटरी के नीचे लगे सीमेंट के दो ब्लॉक पूरी तरह से टूट गए। पटरियों के बीच 2 फीट गहरा गड्ढा हो गया।

दुनिया का छठा प्रोजेक्ट

नवी मुंबई में बन रही देश की पहली समुद्री रेल-टनल

● 7 किलोमीटर लंबी, 35 मंजिला इमारत जितनी गहराई में दौड़ेगी बुलेट ट्रेन

सावली (एजेंसी)। नवी मुंबई के सावली में देश की पहली समुद्री रेल सुरंग बनाई जा रही है। इस सुरंग से देश की पहली बुलेट ट्रेन गुजरेगी। सुरंग बनाने का काम जमीन से 114 मीटर नीचे चल रहा है, यानी इतनी गहराई, जितनी 35 मंजिला ऊंची इमारत होती है। समुद्र के अंदर सुरंग बनाने का यह छठा प्रोजेक्ट है। दुनिया में सबसे ज्यादा 2 समुद्री सुरंगें जापान में हैं। इसके अलावा चीन, नॉर्वे में एक-एक समुद्री सुरंग है। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच भी एक समुद्री सुरंग बनी है।



भारी गर्मी और घुटन के बीच करीब 1,200 मजदूर और इंजीनियर दिन-रात इस काम में जुटे हैं। सावली से शीलफाटा के बीच 4.8 किलोमीटर लंबी सुरंग पहले ही तैयार हो चुकी है। अब समुद्र के अंदर 7 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदी जा रही है, जिसके लिए 3,000 टन भारी मशीन लगातार खुदाई कर रही है। आमतौर पर मेट्रो के आने-जाने के लिए दो अलग सुरंगे बनती हैं, लेकिन यहां एक ही चौड़ी सुरंग के अंदर से दोनों तरफ की बुलेट ट्रेनें एक साथ निकलेंगी।

पानी का दबाव और कंपन रोकना बड़ी चुनौती

विक्रोली से बीकेसी के बीच इमारतों, फ्लाईओवरों को कंपन से बचाने के लिए टीबीएम की गति 4 आरपीएम पर सेट है। जमीन पर रियल-टाइम सेटलमेंट सेंसर 24 घंटे हलचलों की निगरानी कर रहे हैं। पानी का दबाव : गीली मिट्टी और भारी जलदाब के कारण समुद्री सुरंग में पानी भरने का जोखिम है। इससे बचने स्लरी बेस्ड मिक्स शील्ड टीबीएम चल रही है, जो मिट्टी-पानी के गाढ़े घोल की मदद से खुदाई कर रही है। 13.6 मीटर व्यास वाली विशाल सुरंग एनएटीएम तकनीक से खोदते तो इसके ढहने की आशंका ज्यादा थी। इसलिए टीबीएम से खुदाई के साथ ही कंक्रीट रिंग सेगमेंट्स और वाटरप्रूफ सीलिंग लगा रहे हैं।

राहुल गांधी ने पीएम को फिर दी बहस की चुनौती

बोले-मोदी देशद्रोही, ट्रम्प के कहने पर काम कर रहे

संगरूर (एजेंसी)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैंने पीएम नरेंद्र मोदी को डिबेट की चुनौती दी है। मैंने उन्हें कहा है कि कहीं भी आकर मेरे साथ डिबेट कर लो, लेकिन वह मेरे सामने आकर बैठ नहीं सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि 5 मिनट में उन्हें देशद्रोही साबित कर दूंगा। मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नियत्रंति कर रहे हैं। ये बात उन्होंने पंजाब के संगरूर में इंसाफ रैली के दौरान कही। संबोधन की शुरुआत में वह पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को स्टेज पर लाए। राहुल गांधी ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला के साथ जो हुआ, वह आज पंजाब में एक फैशन बन गया है। पंजाब में नशा सबसे बड़ा मुद्दा है।



राहुल गांधी ने कहा- कांग्रेस की सरकार बनाइए

राहुल गांधी ने पंजाब के लोगों से कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील करते हुए कहा कि पंजाब को पंजाब की सरकार दीजिए। कांग्रेस की सरकार दीजिए। ऐसी सरकार चुनिए जो नशे के खिलाफ लड़े, ड्रग्स खत्म करे, युवाओं को रोजगार दे, उद्योगों को बचाए और किसानों के साथ खड़ी रहे।

संक्षिप्त समाचार

दिल्ली पुलिस ने करोल बाग में सोना चोरी करने के मामले में तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार किया



अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस ने करोल बाग में सोने के गहने चोरी करने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि चोरी हुए सभी गहने बरामद कर लिए गए हैं। इनका वजन लगभग 400 ग्राम है और इनकी कीमत करीब 45 लाख रुपए है। अधिकारी ने बताया कि एक नवंबर को करोल बाग थाने में सोने के गहने चोरी होने की सूचना मिली। शिकायत के बाद मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए टीम ने जांच शुरू की थी। पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने करोल बाग के बीडनपुरा स्थित एक ज्वेलरी शॉप से करीब 400 ग्राम वजन का सोना खरीदा। शाम करीब 6 बजे गहने लेने के बाद उसने उन्हें एक बैग में रखा और बैग को अपनी मोटरसाइकिल के पीछे लटका दिया। इसके बाद वह ब्रिटानिया चौक स्थित अपने कार्यालय की ओर निकल पड़ा। जब वह अपने कार्यालय पहुंचा, तो उसने देखा कि बैग की चेन खुली हुई थी और सोने के गहने गायब थे। इस संबंध में, करोल बाग थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई।

अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपराधियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया। जांच के दौरान, आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की गई। फुटेज से पता चला कि बीडनपुरा में बैंक स्ट्रीट के चौराहे पर तीन लोगों ने मिलकर इस चोरी को अंजाम दिया था।

जांच में सामने आया कि आरोपियों में से एक ने यातायात पुलिसकर्मी के रूप में शिकायतकर्ता की मोटरसाइकिल को रोका था, जबकि दूसरे ने चुपके से बैग खोलकर गहने निकाल लिए। तीसरे आरोपी ने इस दौरान निगरानी रखी और अपराध को अंजाम देने में मदद की।

मामले की जांच करते हुए पुलिस ने शुरुआत में दो आरोपियों की पहचान की और मंगलवार को उन्हें आनंद पर्वत इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान, उनके तीसरे साथी की भी पहचान हुई और बाद में उसे भी आनंद पर्वत से ही गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल, दिल्ली पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।

दिल्ली के स्कूल में दर्दनाक हादसा : तीसरी कक्षा की छात्रा कक्षा में बेहोश होकर गिरी, अस्पताल में मृत घोषित



अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में स्थित लवली पब्लिक स्कूल में बुधवार सुबह एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया। स्कूल की तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली 9 वर्षीय बच्ची कक्षा के दौरान अचानक अचेत होकर गिर पड़ी। उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पांडव नगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, 4 नवंबर 2026 की सुबह करीब 09:52 बजे पुलिस को सूचना (पीसीआर कॉल) मिली कि लवली पब्लिक स्कूल की तीसरी कक्षा की एक छात्रा को निर्माण विहार स्थित अस्पताल लाया गया है, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है।

सीसीटीवी में अचानक गिरती दिखी बच्ची

घटना के बाद पुलिस टीम तुरंत सक्रिय हुई और प्रारंभिक पूछताछ के दौरान बच्ची की कक्षा का सीसीटीवी फुटेज खंगाला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि पढ़ाई के दौरान बच्ची अचानक अपनी सीट से नीचे अचेत होकर गिर गई।

परिजनों और स्कूल प्रशासन के दर्ज होंगे बयान

पांडव नगर थाना पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि बच्ची की मौत के सटीक कारणों और परिस्थितियों का पता लगाया जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़ित बच्ची के माता-पिता और स्कूल प्रशासन के अधिकारियों व शिक्षकों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। साथ ही कक्षा के अन्य सीसीटीवी फुटेज और संबंधित साक्ष्यों का भी बारीक से अध्ययन किया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह साफ हो सकेगी।

ओपन चैलेंज, संसद में आइए, बहस करते हैं। , सीएम रेखा गुप्ता ने दी राहुल गांधी को संसद में बहस करने की चुनौती

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संसद में बहस करने की खुली चुनौती दी है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी को चुनौती दी है। रेखा गुप्ता की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा गया, 'राहुल गांधी जी, ओपन चैलेंज। संसद में आइए। बहस करते हैं! 1975 में आपकी दादी ने इमरजेंसी लगाई। विपक्ष को जेल में डाला। प्रेस का मुँह बंद कर दिया। लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। 1984 में आपके पिता प्रधानमंत्री थे, जब दिल्ली में हजारों बेगुनाह सिखों का कत्लेआम हुआ था। कांग्रेस आज भी उस खून से सनी विरासत से बच नहीं पाई है।' दिल्ली की सीएम ने एक्स पोस्ट में आगे लिखा, '2014, 2019 और 2024–लगातार तीन टर्म। चौथा टर्म तो आपका सबसे बड़ा बुरा सपना है। भागना मत! जगह भारत की संसद, नई दिल्ली। वीजा की जरूरत नहीं। '

रेखा गुप्ता की ओर से राहुल गांधी को संसद में बहस की चुनौती तब दी गई, जब उन्होंने मंगलवार की शाम को प्रधानमंत्री को डिबेट करने का चैलेंज किया था। राहुल गांधी के एक्स पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए दिल्ली की सीएम ने संसद में उनसे बहस करने की चुनौती दे दी।

राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था, '24 घंटे हो गए, मोदी जी। मैंने आपको चैलेंज दिया है। आप कहते हैं कि विपक्ष देशद्रोही है। किसी भी स्टेज पर आप जगह चुनिए, डिबेट कीजिए मेरे साथ। देशद्रोही कौन है? विदेशी ताकतों का कनेक्शन किसका है? और किस प्रकार का कनेक्शन है? जल्दी से जल्दी कीजिए, डरिए मत। दोनों मिलेंगे, मीडिया होगी, देश के युवा होंगे, टेबल होगी, एक साइड आप बैठेंगे, एक साइड मैं बैठूंगा। जिसको आप जज बनाना चाहते हैं, बना दीजिए। मोहन भागवत जी को बिठा दीजिए, चलिए। और फिर डिबेट करते हैं। '

राहुल गांधी ने आगे लिखा था, 'सवाल उठेंगे फाइनेंशियल सिस्टम पर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर, यूएस डील कैसे हुई, क्यों हुई, इतनी जल्दी क्यों हुई, सिर्फ आपने क्यों की, कैबिनेट को क्यों नहीं बताया, एपस्टीन-ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जिन पर खुलकर डिस्कशन होगा। आ जाइए, डरिए मत। दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए। आप एलिगेशन लगाते हैं न मेरे ऊपर, आ जाइए, सब साफ हो जाएगा। '

'मस्जिद से एलर्जी है', कदीमी मस्जिद मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली । एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नई दिल्ली में कृषि भवन कंपाउंड में मौजूद सौ साल पुरानी कदीमी मस्जिद को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि उसे मस्जिद से एलर्जी है। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, 'केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट (सीसीएस) के रीडेवलपमेंट के लिए नई दिल्ली में कृषि भवन कंपाउंड में मौजूद 100 वर्ष पुरानी कदीमी मस्जिद को हटाना होगा। सरकार का तर्क है कि मस्जिद 'नाजायज है और सरकारी प्रॉपर्टी के सेक्युलर नेचर के साथ मेल नहीं खाती'। मोदी सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का उद्घाटन भूमि पूजा के साथ किया। साफ है, सेक्युलरिज्म को किसी पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए एक धर्म के रीति-रिवाजों के इस्तेमाल से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे एक ऐसी मस्जिद से एलर्जी है जो 1912 से भी पहले से, कृषि भवन के बनने से बहुत पहले से वहां मौजूद है।' सेंट्रल



असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, 'केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट (सीसीएस) के रीडेवलपमेंट के लिए नई दिल्ली में कृषि भवन कंपाउंड में मौजूद 100 वर्ष पुरानी कदीमी मस्जिद को हटाना होगा। सरकार का तर्क है कि मस्जिद 'नाजायज है और सरकारी प्रॉपर्टी के सेक्युलर नेचर के साथ मेल नहीं खाती'। मोदी सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का उद्घाटन भूमि पूजा के साथ किया। साफ है,

विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कृषि भवन परिसर में स्थित मस्जिद को लेकर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। अपने हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि कृषि भवन में मौजूद मस्जिद सरकारी संपत्ति के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के खिलाफ है और इसे हटाया जाना चाहिए। बीते दिन केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि कृषि भवन परिसर में स्थित कदीमी मस्जिद को हटाने की जरूरत है, ताकि सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट मास्टर प्लान के तहत कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग 4 और 5 का पुनर्विकास हो सके। सरकार का कहना है कि यह निर्माण राष्ट्रीय महत्व की सर्वोपरि जन परियोजना है और प्रोजेक्ट साइट पर फिलहाल मस्जिद मौजूद होने से इसके कार्यान्वयन में बाधा आ रही है।

हलफनामे में केंद्र सरकार ने स्पष्ट तर्क दिया है कि किसी भी केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर की सीमा के भीतर स्थायी धार्मिक ढांचा स्थापित करना, बनाए रखना या दावा करना अस्वीकार्य है और यह सरकारी संपत्ति के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के विपरीत है। सरकार ने कहा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में स्थित सार्वजनिक भूमि पर कोई स्थायी धार्मिक निर्माण नहीं हो सकता। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा कि कृषि भवन और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स धर्मनिरपेक्ष सार्वजनिक परिसर हैं, जो विशेष रूप से सरकारी, प्रशासनिक और जनसेवा कार्यों के लिए समर्पित हैं। ऐसे में परिसर के भीतर धार्मिक ढांचे को बनाए रखना उचित नहीं है। सरकार ने यह भी बताया कि सीसीएस बिल्डिंग 4 और 5 का निर्माण सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान का अहम हिस्सा है। इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट साइट पर मौजूद मस्जिद को हटाना जरूरी है।

केंद्र ने कोर्ट को यह भी जानकारी दी कि कृषि भवन के आसपास दो किलोमीटर के दायरे में शाही मस्जिद जाब्तागंज स्थित है, जो आसपास के किसी भी व्यक्ति को नमाज की पूरी सुविधा प्रदान करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में कृषि भवन परिसर के भीतर अलग से मस्जिद की आवश्यकता नहीं है।

अमेरिकी मिडटर्म चुनावों में डेमोक्रेट्स की जीत से भारत को मिल सकता है फायदा, कच्चे तेल और डॉलर पर रह सकती है नजर

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत ने वैश्विक वित्तीय बाजारों में हलचल तेज कर दी है। विश्लेषकों का कहना है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के बेहतर प्रदर्शन से कच्चे तेल की कीमतों, अमेरिकी व्यापार नीतियों, प्रमुख उद्योगों के नियामकीय ढांचे और वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य पर असर पड़ सकता है। इसका प्रभाव भारत सहित दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं पर भी देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, चुनावी समीकरणों में बदलाव की संभावना के चलते अमेरिकी डॉलर इंडेक्स और ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड में तेज गिरावट दर्ज की गई है। बाजार इस संभावना को भी ध्यान में रख रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के मजबूत स्थिति में आने से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान से जुड़े तनाव को कम करने का दबाव बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आ सकती है। हालांकि डेमोक्रेट्स की जीत के बाद कच्चे तेल की कीमतों में बुधवार को गिरावट दर्ज की गई। खबर लिखे जाने तक (दोपहर 1.54 बजे के करीब) डब्ल्यूटीआई क्रूड 0.33 प्रतिशत की गिरावट के साथ 95.82 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता नजर आया, तो वहीं ब्रेंट क्रूड 0.43 प्रतिशत की गिरावट के साथ 103.2 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करती नजर आई। विशेषज्ञों का कहना है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत का भारत के लिए सबसे बड़ा लाभ कम कच्चे तेल की कीमतों के रूप में सामने आ सकता है। कम तेल कीमतों से आयात बिल घटेगा, रुपए पर दबाव कम होगा और मुद्रास्फीति नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही कमजोर अमेरिकी डॉलर और नरम ट्रेजरी यील्ड विदेशी निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता बढ़ा सकते हैं, जिससे भारतीय बाजारों में निवेश प्रवाह को समर्थन मिल सकता है। हालांकि विश्लेषकों का यह भी कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर तत्काल कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने की संभावना कम है। चुनाव परिणामों के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति के पास विदेश नीति और व्यापार से जुड़े कई मामलों में व्यापक कार्यकारी अधिकार बने रहेंगे। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वित्तीय सेवाओं, ऊर्जा और कुछ प्रौद्योगिकी कंपनियों पर अल्पकालिक दबाव बन सकता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रभाव बढ़ने की स्थिति में सख्त नियामकीय निगरानी और भविष्य में करों में वृद्धि की आशंका बढ़ सकती है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने से ऊर्जा कंपनियों की आय पर भी असर पड़ सकता है। विश्लेषकों का यह भी मानना है कि डेमोक्रेटिक नियंत्रण वाली कांग्रेस राष्ट्रपति ट्रंप की शुल्क (टैरिफ) नीतियों पर अधिक निगरानी रख सकती है और कुछ मामलों में विधायी चुनौतियां पेश कर सकती है। हालांकि टैरिफ व्यवस्था में तत्काल बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, क्योंकि व्यापार नीति के कई महत्वपूर्ण अधिकार राष्ट्रपति के पास ही बने रहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) क्षेत्र को लेकर विशेषज्ञ अभी भी सकारात्मक नजरिया रखते हैं। उनका मानना है कि डेटा सेंटर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई निवेश आने वाले समय में भी जारी रहेंगे। हालांकि सरकारों की भूमिका इन क्षेत्रों में नियमन और बुनियादी ढांचा विकास के मामलों में अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक, वैश्विक बाजारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत का आकार कितना बड़ा होता है,

दो से अधिक बच्चे होने पर चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानून अब प्रासंगिक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि दो से अधिक बच्चे होने पर दंड देने वाले कानूनों की प्रासंगिकता खत्म हो गई है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि भारत में प्रजनन दर लगातार घट रही है। ऐसे में इन कानूनों का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। इनकी फिर से समीक्षा की जरूरत है। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने महाराष्ट्र के काकोडा ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच मंगला भीमराव की अयोग्यता को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की, जिन्हें तीसरा बच्चा होने के कारण चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया था।

अपनी टिप्पणी में कोर्ट ने कहा, 'पिछले दो दशकों में भारत की जनसांख्यिकीय स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। पिछले कुछ दशकों में आए जनसांख्यिकीय बदलावों के कारण जनसंख्या विस्फोट का डर अब नहीं रहा। इसका प्रमाण यह है कि प्रजनन दर 3 से घटकर 1.9 पर आ गई है। इसलिए, दो से अधिक बच्चे होने पर चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने वाले कानून, मौजूदा



हालात में शायद अब प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। '

इसलिए, अदालत ने महाराष्ट्र के एक कानून के तहत पूर्व सरपंच मंगला भीमराव के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 2003 के जावेद बनाम हरियाणा सरकार मामले में दिए गए फैसले को आगे समीक्षा के बड़ी बेंच के पास भेज दिया। उस फैसले में तीन जजों की पीठ ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के उस प्रावधान को सही ठहराया था, जिसके तहत दो से अधिक जीवित बच्चे होने पर व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता था।

कोर्ट ने बताया कि जब 'जावेद' मामले में फैसला आया था, तब भारत की कुल प्रजनन दर लगभग तीन बच्चे प्रति महिला थी, जिससे जनसंख्या नियंत्रण एक अहम नीतिगत मुद्दा बन गया था। हालांकि, तब से जनसांख्यिकीय संकेतकों में काफी बदलाव आया है और पूरे देश में प्रजनन दर लगातार घट रही है।

दिवाली से पहले प्रदूषण का कहर

दिल्ली एनसीआर में हवा हुई बहुत खराब, कहां कितना दर्ज किया गया एक्यूआई

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। दिवाली से पहले ही दिल्ली-एनसीआर की हवा की हालत काफी खराब हो चुकी है। नवंबर के पहले ही सप्ताह में वायु प्रदूषण ने विकराल रूप ले लिया। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में हवा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सुबह आठ बजे आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का एक्यूआई 377, नोएडा में 314, ग्रेटर नोएडा में 266, गाजियाबाद में 236, गुरुग्राम में 324 एक्यूआई दर्ज किया गया।

दिल्ली के कई इलाकों में 400 पार एक्यूआई

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों को मुताबिक, अलीपुर में 422, आनंद विहार में 302, अशोक विहार 348, आया नगर 382, बदरपुर 334, बवाना 411, चांदनी चौक 370, द्वारका सेक्टर-8 में 400, आईआईआई एयरपोर्ट टर्मिनल-3 पर 360, आईटीओ 421, जहांगीरपुरी 450, लोधी रोड 316, मुंडका 443, ओखला फेज-2 में 414, पटपड़गंज में 419, पंजाबी बाग 456, रोहिणी 436, डीटीयू 435, विवेक विहार 435, नरेली 419, नॉर्थ कैंपस 416 एक्यूआई दर्ज किया गया।



नोएडा के सेक्टर 62 का बुरा हाल

सीपीसीबी के सुबह आंकड़ों के अनुसार, नोएडा के सेक्टर 110 में 349, सेक्टर 116 में 261, सेक्टर 125 में 243, सेक्टर 150 में 351, सेक्टर-1 में 244, सेक्टर 39 में 321, सेक्टर 62 में 426 एक्यूआई दर्ज किया गया।

गाजियाबाद में 300 पार एक्यूआई

गाजियाबाद में हवा की हालत खराब है। जिले के कई इलाकों में एक्यूआई 300 पार पहुंच गया है। लोनी में 304 , वेव सिटी में 312 और संजय नगर में 308 एक्यूआई दर्ज किया गया।

मंगलवार को दिल्ली में इतना रहा एक्यूआई

प्रदूषण के मामले में जहांगीरपुरी 461 एक्यूआई के साथ राजधानी में सबसे ऊपर रहा। इसके बाद रोहिणी में 447, पंजाबी बाग में 445, डीटीयू में 442 और अलीपुर में 430 एक्यूआई दर्ज किया गया। मुंडका और नरेला में 422, बवाना में 420, विवेक विहार में 426 और नॉर्थ कैंपस में 404 एक्यूआई रहा।

सबसे चौंकाने वाला बदलाव डीटीयू में देखने को मिला। यहां एक्यूआई पिछले स्तर 315 से बढ़कर 442 पहुंच गया। महज एक रात और दिन के भीतर 127 अंकों की बढ़ोतरी ने हवा की बिगड़ती स्थिति को उजागर कर दिया। इसी तरह शादीपुर में भी एक्यूआई 228 से बढ़कर 345 हो गया। यानी जिन इलाकों में प्रदूषण पहले खराब स्तर पर था, वहां भी स्थिति तेजी से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई।

दिल्ली पुलिस ने रूसी विदेश मंत्री का 'फर्जी' वीडियो शेयर करने पर प्रशांत भूषण के खिलाफ दर्ज की एफआईआर

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का कथित रूप से डॉक्टर्ड वीडियो शेयर करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, यह मामला मंगलवार (3 नवंबर) को साइबर पेट्रोलिंग के दौरान सामने आया। टीम ने एक सोशल मीडिया पोस्ट देखा, जिसमें आरोप लगाया गया था कि रूसी विदेश मंत्री का कथित तौर पर छेड़छाड़ किया गया वीडियो भूषण के हैंडल से शेयर किया गया था। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, '3 नवंबर को, साइबर पेट्रोलिंग के दौरान, यह पता चला कि एक सोशल मीडिया हैंडल ने दावा किया है कि रूसी विदेश मंत्री का एक कथित डॉक्टर्ड वीडियो, जो भारत के खिलाफ है, प्रशांत भूषण के हैंडल से शेयर किया गया था। '

दिलली पुलिस ने कहा, 'वीडियो के माध्यम से भ्रामक, मानहानिकारक और भड़काऊ सामग्री प्रसारित कर सार्वजनिक उपद्रव व अफवाहें फैलाने का आरोप है। इस संबंध में बीएनएस की धारा 336(4), 353(1)(सी), 356 और 340(2) के तहत एफआईआर और आईटी एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है।' अधिकारियों ने बताया कि यह एफआईआर स्पेशल सेल पुलिस थाने में दर्ज की गई है।

इससे पहले, विदेश मंत्रालय (एमईए) की फैक्ट-चेक यूनिट ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के कथित वीडियो के संबंध में बयान दिया और इसे फर्जी बताया। शेयर किए गए डॉक्टर्ड वीडियो में रूसी विदेश मंत्री भारत के अंदरूनी मामलों और तेल खरीद पर आलोचना करते हुए दिख रहे थे।

प्रशांत भूषण की ओर से शेयर किए गए वीडियो के तथ्यों को रूसी दूतावास ने भी खारिज किया था। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि क्लिप पूरी तरह से मनगढ़ंत थी। एमईए ने एक पोस्ट में लिखा, 'फेक अलर्ट! इस पोस्ट में इस्तेमाल किया जा रहा रूसी विदेश मंत्री का वीडियो फर्जी है! '

रामलीला मैदान में आयोजित रैली से गैरहाजिर रहे पदाधिकारियों के खिलाफ कांग्रेस का एक्शन, 83 लोग निलंबित

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली । दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को इंडिया गठबंधन की ओर से बुलाई गई 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली में गैरहाजिर रहे पदाधिकारियों के खिलाफ कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लिया है। पदाधिकारियों को गैरमौजूदगी भारी पड़ी है। भारतीय युवा कांग्रेस की ओर से तीन राज्यों में बड़ा एक्शन लिया गया है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 60, हरियाणा में 10 और हिमाचल प्रदेश में 13 युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों सहित कुल 83 लोगों को निलंबित कर दिया है। कांग्रेस की ओर से की गई इस कार्रवाई में प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव से लेकर जिलाध्यक्ष तक के नेता शामिल हैं। रैली में भीड़ जुटाने के दावों के बीच अब संगठन के भीतर ही जवाबदेही तय करने का संदेश दिया जा रहा है।

बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' की रैली को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने 'वोट चोरी' का आरोप लगाते हुए कहा था कि ज्ञानेश कुमार को इसके लिए मुकदमे का सामना करना पड़ेगा और उन्हें जेल जाना होगा।



राहुल गांधी ने कहा था कि देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए यह लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया था कि ज्ञानेश कुमार ने जो किया है, वह सामान्य चोरी नहीं, बल्कि कानूनी भाषा में 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' (दुर्लभतम) श्रेणी का मामला है। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर ईवीएम के इस्तेमाल और मतदाता सूची से 13.5 करोड़ नाम हटाने के जरिए वोट चोरी करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था, 'प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए ज्ञानेश कुमार ने जो किया है, वह देशद्रोह और हर नागरिक की आवाज की चोरी के समान है। '

राहुल गांधी ने कहा था कि यहां जुटे लोग संदेश दे रहे हैं कि कोई कितना भी शक्तिशाली और अमीर क्यों न हो, वह संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। संविधान सर्वोच्च है। उन्होंने इस रैली को लोकतंत्र बचाने के लिए एकजुटता और सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन बताया।

उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने देश की आत्मा, लोकतंत्र और संविधान पर हमला किया है, लेकिन हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। '

संक्षिप्त समाचार

गाजियाबाद में 37वें अखिल भारतीय खेलकूद समारोह का समापन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित



अनप्लग इंडिया।

गाजियाबाद। गाजियाबाद में आयोजित 37वें अखिल भारतीय खेलकूद समारोह का बुधवार को समापन हो गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड पहुंचे। उन्होंने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। विद्या भारती की ओर से आयोजित इस खेल समारोह में देश के अलग-अलग राज्यों से करीब 850 खिलाड़ियों ने भाग लिया। चार दिवसीय आयोजन के दौरान शुरुआती तीन दिनों तक खिलाड़ियों ने परेड ग्राउंड में विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपना दमखम दिखाया। समारोह के अंतिम दिन महिला खिलाड़ियों ने भी पदक हासिल किए।

पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता हासिल करने के लिए लगातार अभ्यास करना जरूरी है। उन्होंने खिलाड़ियों को अपनी तैयारी में नियमितता बनाए रखने की सलाह दी।

मुख्यमंत्री ने सफलता के लिए तीन प्रमुख बातें बताईं–

नियमित रूप से अभ्यास करें और इसे बीच में न छोड़ें।

बड़ी सफलता एक दिन की मेहनत से हासिल नहीं होती।

रोजाना की छोटी-छोटी कोशिशें ही बड़े लक्ष्य तक पहुंचाती हैं।

देशभर के 850 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा

विद्या भारती की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों से जुड़े करीब 850 खिलाड़ियों ने भाग लिया। तीन दिनों तक चली खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया।

आयोजन के अंतिम दिन महिला खिलाड़ियों ने भी पदक जीतकर अपनी उपलब्धि दर्ज कराई। समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों को आगे भी मेहनत और अभ्यास जारी रखने के लिए प्रेरित किया।

पटाखा दुकानों पर सुरक्षा जांचेगा अग्निशमन विभाग

अनप्लग इंडिया

नोएडा। दीपावली पर पटाखों की बिक्री और भंडारण को लेकर अग्निशमन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पटाखा दुकानों पर आग से बचाव के इंतजामों की जांच की जाएगी। सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं पर कार्रवाई हो सकती है। बुधवार को सेक्टर-2 स्थित फायर स्टेशन पर पुलिस और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने पटाखा विक्रेताओं के साथ बैठक कर सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश दिए।

डीसीपी नोएडा प्रीति यादव की ओर से आयोजित बैठक में एडीसीपी नोएडा अभय कुमार मिश्र और मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार मौजूद रहे। अधिकारियों ने पटाखों के सुरक्षित भंडारण, रखरखाव और बिक्री के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर चर्चा की। विक्रेताओं को बताया गया कि पटाखों की बिक्री के दौरान अग्नि सुरक्षा के निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल निर्धारित और अधिकृत स्थलों पर ही की जाएगी। सभी दुकानों और बिक्री स्थलों पर पर्याप्त अग्निशमन उपकरण रखने होंगे। आग लगने की स्थिति में तत्काल बचाव के लिए जरूरी इंतजाम पहले से करने होंगे। दुकानों में ज्वलनशील सामग्री का अनावश्यक भंडारण नहीं करने की हिदायत दी गई। इसके अलावा बिजली के तारों, कनेक्शन और उपकरणों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया।

बैठक में अधिकारियों ने कहा कि पटाखों के भंडारण और बिक्री में छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। ऐसे में दुकानदार सुरक्षा इंतजामों को गंभीरता से लें। प्रशासन और अग्निशमन विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। किसी संदिग्ध गतिविधि या आग लगने की आशंका होने पर तत्काल संबंधित विभाग को सूचना दें। दीपावली खुशियों का त्योहार है। इसे सुरक्षित माहौल में मनाने के लिए सभी की जिम्मेदारी है। पुलिस और अग्निशमन विभाग आम लोगों की सुरक्षा के लिए सतर्क है। विक्रेताओं से भी नियमों का पालन कर सुरक्षित दीपावली सुनिश्चित करने में सहयोग मांगा गया।

दरवाजे-खिड़की बनाने वाली फैक्टरी से लाखों का सामान

अनप्लग इंडिया

नोएडा। सेक्टर-65 स्थित एल्युमिनियम दरवाजे, खिड़की का काम करने वाली फैक्टरी से चोर कीमती सामान चोरी कर ले गए। वारदात के समय रात में फैक्टरी बंद थी। फैक्टरी मालिक ने मंगलवार को फेज-तीन थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज कराया है।सेक्टर-65 के ए ब्लॉक में सुमित गांधी की पीकेजी डिजाइंस के नाम से फैक्टरी है। फैक्टरी प्रबंधन एल्युमिनियम गेट, खिड़की का काम करता है। पांच अक्तूबर की रात चोरों ने फैक्टरी पर धावा बोला। चोर फैक्टरी परिसर से कंप्यूटर सिस्टम, हार्ड डिस्क, एल्युमिनियम कटर, सामग्री, तैयार माल, कच्चा माल, औजार, प्रिंट हेड और कीमती सामान चोरी कर ले गए। अगले दिन फैक्टरी पहुंचने पर चोरी का पता चला। परिसर के अंदर सामान फैला हुआ था। उन्होंने सामान को आसपास ढूंढा, लेकिन सामान नहीं मिला। सुमित ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की, लेकिन चोरों का पता नहीं चला। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

बेसमेंट के कचरे में लगी आग, मेंटेनेंस टीम ने समय रहते पाया काबू

अनप्लग इंडिया

ग्रेटर नोएडा। सेक्टर ईटा-2 स्थित मिग्सन विलासा सोसाइटी के बेसमेंट में मंगलवार देर रात कचरे में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही मेंटेनेंस टीम मौके पर पहुंची और अग्निशमन उपकरणों की मदद से आग पर काबू पा लिया। समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया। सोसाइटी के टावरों में बनी शाफ्ट में कचरा जमा हो रहा था। इसी कचरे में किसी चिंगारी या जलती हुई वस्तु के संपर्क में आने से आग लग गई। आशंका जताई जा रही है कि किसी बच्चे ने पटाखा जलाकर या फेंककर आग लगा दी होगी। आग लगते ही निवासियों ने मेंटेनेंस रूम को सूचना दी। इसके बाद टीम ने फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग बुझाई। देर रात लोगों ने भी आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत की। सोसाइटी के एओए सचिव मुकुल ने बताया कि आग लगने की जानकारी मिलते ही मेंटेनेंस टीम ने तुरंत कार्रवाई की। अग्निशमन उपकरणों की मदद से कुछ ही देर में आग बुझा दी गई। समय पर आग पर काबू पा लेने से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बिल्डर प्रबंधन ने बताया कि सोसाइटी में आग लगने की घटना के कारणों की जांच सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से की जा रही है। शुरुआती आशंका है कि फ्लैटों के बीच शाफ्ट में जमा कूड़े में जलती सिगरेट फेंके जाने से आग लगी हो सकती है, हालांकि इसकी पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी।

'जीएनआईओटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में फ्रेशर्स पार्टी का भव्य आयोजन, नए विद्यार्थियों का हुआ जोरदार स्वागत'

अनप्लग इंडिया

नोएडा। नॉलिज पार्क स्थित जीएनआईओटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नवागंतुक विद्यार्थियों के स्वागत हेतु भव्य फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया गया। फ्रेशर पार्टी का उद्देश्य नए छात्रों का स्वागत करना, उन्हें नए वातावरण से परिचित कराना और उनके बीच आत्मीयता का भाव विकसित करना होता है। कार्यक्रम में ग्रुप के विभिन्न कॉलेजों एवं विभागों के विद्यार्थी उत्साह, खुशी और जोश से सराबोर दिखे।





कार्यक्रम के दौरान जीएनआईओटी कॉलेज समूह के चेयरमैन डॉ. राजेश गुप्ता, वाइस चेयरमैन श्री गौरव गुप्?ता , मैनेजमेंट सदस्य श्री बजरंग लाल गुप्ता , श्री जे. एस. रावल , ग्रुप के सभी संस्थानों के निदेशक डा. धीरज गुप्ता, डा. सविता मोहन, डा. अंशुल शर्मा, प्रो. मन्जू राजपूत, डा. कल्पना रानी जायस, डा. नीति श्रीवास्तव वाईस प्रेसिडेंट श्री टी. एन. चौरसिया, श्री सुशील भारद्वाज, श्री नितिन मेहरा, ट्रेनिंग- प्लेसमेंट निदेशक डा. बबीता जी. कटारिया एवं ग्रुप रजिस्ट्रार श्री अनिल मधवाल सहित सभी संस्थानों के डीन, विभागाध्यक्ष एवं शिक्षकगण उपस्थित रहे!

मंच पर विभिन्न सांस्कृतिक, मनोरंजक और आधुनिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। छात्रों ने ग्रुप डांस, सोलो सिंगिंग, इंस्ट्रुमेंटल परफॉर्मेंस, फैशन शो वॉक, स्किट एवं नाट्य मंचन जैसी कई शानदार प्रस्तुतियों से माहौल को जीवंत बना दिया। विशेष रूप से फैशन शो में छात्रों ने अपने कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और स्टाइल का अद्भुत प्रदर्शन किया।

विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों एवं प्रतियोगिताओं के आधार पर विभिन्न संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों से मिस्टर एवं मिस फ्रेशर का चयन किया गया! बीटेक से शिवांश एवं एकता , बीसीए- एकेटीयू से विक्की एवं तन्वी सिंह, एमसीए से सरवजीत चौहान एवं महिमा उपाध्याय , बीबीए-एकेटीयू से अर्पित एवं प्रियांशी, एमबीए-इंटीग्रेटिड से आयुष एवं हर्षिता , एमबीए से नित्यानंद एवं भूमिका , बीबीए से साहिल एवं महक , बीसीए से वंश एवं श्रेया, बीकॉम से आयुष एवं साक्षी सिंह , एलएलबी से हर्ष एवं काम्या , नर्सिंग से आयुष एवं इशिता तथा फार्मेसी से आर्यन खान एवं कीर्तिका को मिस्टर एवं मिस फ्रेशर चुना गया!

इस अवसर पर सभी चयनित एवं प्रतिभागी विद्यार्थियों तथा कार्यक्रम आयोजकों को बधाई देते हुए ग्रुप के चेयरमैन डॉ. राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि जीएनआईओटी केवल शिक्षा प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर भी विशेष ध्यान देता है। संस्थान का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक, सामाजिक एवं व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से एक कुशल एवं आत्मविश्वासी व्यक्तित्व के रूप में विकसित करना है और ऐसे आयोजन विद्यार्थियों को एक-दूसरे से जुड़ने, अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने तथा संस्थान के साथ एक नई शुरुआत करने का अवसर प्रदान करते हैं!

कार्यक्रम के अन्त में मशहूर सिंगर आकाश चौहान का लाइव शो आयोजित किया गया। आकाश चौहान ने एक के बाद एक बेहतरीन प्रस्?तुति देकर युवाओं में जोश भर दिया। कार्यक्रम के दौरान युवाओं में आकाश की दीवानगी देखने को मिली। कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में छात्रों ने देर तक कार्यक्रम का आनंद लिया और इस दौरान सभी ने युवाओं के जोश का सराहा।

नोएडा के गेझा गांव में 6 करोड़ रुपये से विकसित होगा ब्रह्मसरोवर, बोटिंग का भी मिलेगा मौका

अनप्लग इंडिया

नोएडा। नोएडा के लोगों को जल्द ही परिवार और दोस्तों के साथ घूमने-फिरने के लिए एक नया आकर्षक पर्यटन स्थल मिलने जा रहा है। गेझा गांव में स्थित पुराने तालाब को आधुनिक सुविधाओं से युक्त ब्रह्मसरोवर के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की गई है। करीब 1.8 एकड़ क्षेत्र में बनने वाली इस परियोजना पर लगभग 6 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

नोएडा प्राधिकरण की इस योजना के तहत तालाब का कायाकल्प कर उसे खूबसूरत पिकनिक स्पॉट का रूप दिया जाएगा। परियोजना का डिजाइन सलाहकार कंपनी तैयार कर चुकी है। प्रस्तावित डिजाइन में सरोवर के चारों ओर हरियाली, आकर्षक लैंडस्केपिंग और रंग-बिरंगे फूलों के पौधे लगाने की व्यवस्था की गई है।

यहां आने वाले लोगों के बैठने के लिए जगह-जगह बेंच बनाई जाएंगी। साथ ही पूरे सरोवर के चारों तरफ वॉकिंग ट्रैक तैयार किया जाएगा। इससे लोग सुबह-शाम टहलने के साथ प्राकृतिक वातावरण में समय बिता सकेंगे।

बोटिंग की सुविधा भी होगी आकर्षण का केंद्र

गेझा गांव के ब्रह्मसरोवर को खास बनाने के लिए यहां बोटिंग की सुविधा शुरू करने की भी योजना है। इसके शुरू होने से लोगों को परिवार के साथ नौकायन का आनंद लेने का अवसर मिल सकता है। हालांकि बोटिंग की सुविधा निर्माण पूरा होने के बाद उपलब्ध व्यवस्थाओं और जरूरत के अनुसार शुरू की जाएगी।

16 नवंबर तक जमा होंगे टेंडर, एक साल में पूरा करना होगा निर्माण

परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने टेंडर जारी कर दिया है। इच्छुक निर्माण कंपनियां 16 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगी। इसके बाद 17 नवंबर को कम लागत वाली कंपनी का चयन किया जाएगा। चयनित एजेंसी को निर्माण कार्य पूरा करने के लिए एक साल का समय दिया जाएगा।



सेक्टर-164 और 107 में भी विकसित हो रहे जलाशय

नोएडा में पुराने तालाबों को नया स्वरूप देने और शहर में हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए दूसरी परियोजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। सेक्टर-164 में एक अन्य सरोवर का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि सेक्टर-107 में पुष्करिणी तालाब को विकसित किया जा रहा है।

इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहर में जलाशयों का संरक्षण करने के साथ लोगों को मनोरंजन, सैर-सपाटे और परिवार के साथ समय बिताने के लिए बेहतर सार्वजनिक स्थान उपलब्ध कराना है।

गत्ते और कार परफ्यूम बनाने वाली फैक्टरी में भीषण आग

छह दमकल गाड़ियों ने पाया काबू

अनप्लग इंडिया

गाजियाबाद। ट्रॉनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र में बुधवार तड़के गत्ते और कार परफ्यूम बनाने वाली फैक्टरी में भीषण आग लग गई। आग फैक्टरी के प्रथम तल पर पूरे हिस्से में फैल गई। सूचना मिलने पर लोनी फायर स्टेशन से तीन दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग की गंभीरता को देखते हुए वैशाली, साहिबाबाद और बागपत के खेकड़ा फायर स्टेशन से भी एक-एक दमकल गाड़ी बुलाई गई। करीब साढ़े तीन घंटे की मशक्कत के बाद छह दमकल गाड़ियों की मदद से सुबह 7:30 बजे आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी सौरभ कुमार सिंह के अनुसार, बुधवार सुबह 4:24 बजे ट्रॉनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर बी-3 स्थित प्लॉट नंबर डी-4 पर संचालित कुमार पैकर्स फैक्टरी में आग लगने की सूचना मिली थी। फैक्टरी के स्वामी मनोज कुमार हैं। सूचना मिलते ही लोनी फायर स्टेशन से तीन दमकल गाड़ियां घटनास्थल के लिए रवाना की गईं। दमकलकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर देखा कि साढ़े तीन मंजिला इमारत के प्रथम तल पर आग पूरी तरह फैल चुकी थी। फैक्टरी के कर्मचारी वहां लगे अग्निशमन उपकरणों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किए।



दमकलकर्मियों ने जीने के रास्ते और बगल की फैक्टरी की छत से पानी की लाइन बिछाकर दोनों तरफ से आग बुझाने का काम शुरू किया। साथ ही आग को इमारत के अन्य तलों तक फैलने से रोकने के प्रयास किए गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वैशाली, साहिबाबाद और खेकड़ा फायर स्टेशन से भी दमकल गाड़ियां बुला ली गईं। सुबह 7:30 बजे तक आग पूरी तरह बुझा दी गई। इसके बाद फैक्टरी में रखे सामान को हटाकर उसकी जांच की गई, ताकि नीचे सुलग रही आग और धुएं को भी पूरी तरह शांत किया जा सके।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जाम से मिलेगी राहत

गौड़ अंडरपास का कल से ट्रायल, सीएम योगी कर सकते हैं लोकार्पण

अनप्लग इंडिया

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चार मूर्ति चौक पर बना अंडरपास कल सुबह से ट्रायल के लिए खुल जाएगा। ऐसे में वाहनों की आवाजाही हनुमान मंदिर रोटरी से तिगरी, गाजियाबाद की तरफ शुरू हो जाएगी। 12 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका औपचारिक लोकार्पण करेंगे जिसके बाद अंडरपास पूरी तरह खोल दिया जाएगा। एसीईओ सुमित यादव ने बताया कि अभी ट्रायल के लिए छह लेन के गौड़ अंडरपास को खोला जा रहा है। इससे अगर कोई कमी अंडरपास में रह गई होगी तो उसे समय रहते दूर कर लिया जाएगा। दीपावली से पहले ही यह अंडरपास शुरू किया जाना था। ऐसे में इससे अभी वाहनों की आवाजाही शुरू करा दी जा रही है। इससे करीब पांच लाख लोगों को सीधे तौर पर फायदा होगा। टेकजोन-4, एफएनजी, सेक्टर-1, सेक्टर-2, सूरजपुर-कासना रोड से आने वाले वाहन सीधे गाजियाबाद, तिगरी, गौड़ सिटी की तरफ बिना जाम में फंसे गुजर सकेंगे। सीईओ रवि कुमार एनजी का कहना है कि अंडरपास से चार मूर्ति चौराहा पर जाम में फंसने की बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। करीब 100 करोड़ रुपये खर्च कर यह अंडरपास ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बनाया है। बारिश से बचाव के लिए जरूरी शेड भी यहां लगाए गए हैं। इससे जलभराव की भी समस्या नहीं होगी। रात के समय अंडरपास में अंधेरा नहीं हो, इसके लिए पर्याप्त रौशनी का इंतजाम भी रहेगा।



अंडरपास से गुजरना सुखद हो, इसके लिए पर्यावरण, विकास को समर्पित पेंटिंग भी अंदर कराई गई है। अंडरपास के ऊपर भी चार मूर्ति चौक का आकार छोटा कराया गया है जिससे अतिरिक्त जगह 130 मीटर रोड से गुजरने वाले वाहनों को मिल सकेगी। इससे जाम से निजात यहां भी मिलेगी।

92 करोड़ रुपये खर्च कर हो रहा निर्माण

2024 की शुरुआत में अंडरपास का निर्माण शुरू हुआ। शुरुआत में की करीब 60 करोड़ रुपये लागत इसकी बताई गई थी जोकि टेंडर प्रक्रिया के समय संशोधित होकर82 करोड़ रुपये हो गई। बिजली लाइन और अन्य यूटिलिटी शिफ्ट करने की लागत सहित इस अंडरपास पर करीब 92 करोड़ रुपये हो गई। इस काम को 18 महीने में पूरा कर लिया जाना था। ऐसे में 2026 की शुरुआत में इस अंडरपास को शुरु हो जाना चाहिए था। काम में देरी को देखते हुए बाद में तीन बार इसकी तारीख बढ़ी। अब यह अंडरपास उपयोग में आ सकेगा। सात करोड़ रुपये की कीमत से शेड का काम अंतिम समय में जुड़ने से लागत करीब 100 करोड़ रुपये हो गई।

नोएडा के पार्क में पेड़ से लटका मिला शव:टहलने गए लोगों ने देखा, गले पर रस्सी के निशान मिले, यहीं रहकर मजदूरी करता था



अनप्लग इंडिया

गाजियाबाद। नोएडा के सेक्टर-69 स्थित एक पार्क में युवक का शव पेड़ से लटका मिला। सुबह सैर करने आए लोगों ने इसकी जानकारी डायल-112 को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आसपास जानकारी करने पर उसकी पहचान प्रभाकर (23) पुत्र राम किशन लाल के रूप में हुई। प्रभाकर गढ़ी गोलचक्कर के पास रहता था। वह मूल रूप से फर्रुखाबाद का रहने वाला था। इसके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

किसी तरह की चोट के निशा नहीं

शुरुआती जांच में मृतक के शरीर पर चोट के निशान नहीं है। गले में रस्सी के निशान हैं। समझा जा रहा है फंदा लगाने के बाद दम घुटने से मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा।

पुलिस ने बताया कि प्रभाकर मजदूरी करता था। उसके पिता भी मजदूरी करते हैं। किसी बात को लेकर को लेकर वो काफी दिनों से परेशान था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने प्रभाकर का फोन जब्त किया है। उससे जानकारी की जा रही है।

दो हजार से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा में रहेंगे, इलाका नो-ड्रोन जोन घोषित

अनप्लग इंडिया

गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन में पांच नवंबर को प्रस्तावित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पदयात्रा को लेकर कमिश्नरेट पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री करीब 1400 मीटर पैदल चलकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे। बुधवार को पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर रिहर्सल की। कार्यक्रम में दो हजार से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा की कमान संभालेंगे। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने बहुस्तरीय व्यवस्था की है। पदयात्रा मार्ग से लेकर कार्यक्रम स्थल तक पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। आसपास की सोसाइटी की छतों पर भी असलहों से लैस पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। यह जवान ऊंचाई वाले स्थानों से आसपास के क्षेत्र पर नजर रखेंगे, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। एडिशनल सीपी कानून-व्यवस्था राजकरन नैय्यर ने बताया कि कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दो हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और एसीपी स्तर के अधिकारी भी अलग-अलग प्वाइंट पर तैनात रहेंगे। मंच के आसपास भी एसीपी की ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत स्वान दस्ते और बम निरोधक दस्ते भी सक्रिय रहेंगे। ये टीमें कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में जांच करेंगी। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

सुरक्षा व्यवस्था के तहत कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्र को नो-ड्रोन जोन घोषित किया गया है। प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की ओर से लोगों को निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखेंगी। इसके अलावा पदयात्रा मार्ग पर भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए भी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।

यातायात डायवर्जन और बंद मार्ग

रोटरी गोल चक्कर से एएलटी तक आवागमन बंद

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए यातायात पुलिस ने विशेष डायवर्जन प्लान लागू किया है। एडीसीपी ट्रैफिक वरुण कुमार सिंह ने बताया कि पांच नवंबर को सुबह सात बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक डायवर्जन प्रभावी रहेगा। रोटरी गोल चक्कर से एएलटी तक और एएलटी से रोटरी गोल चक्कर तक वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। डायमंड फ्लाईओवर रेडलाइट से हापुड़ चुंगी की ओर कमर्शियल वाहन नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा हिंडन मेट्रो स्टेशन से रोटरी गोल चक्कर की ओर भी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।

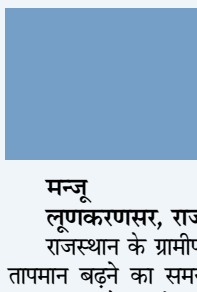
अन्य प्रतिबंधित मार्ग और वैकल्पिक रास्ते-इन रास्तों पर भी रहेगा प्रतिबंध

एडीसीपी ट्रैफिक के मुताबिक करहेड़ा तिराहे से नागद्वार और नागद्वार से रोटरी गोल चक्कर की ओर वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी। करण गेट और लाजपत नगर की ओर से हिंडन एयरफोर्स गोल चक्कर की तरफ भी आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। दुहाई ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से गाजियाबाद की ओर कमर्शियल वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे प्रतिबंधित मार्गों पर जाने से बचें और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। कार्यक्रम के दौरान राजनगर एक्सटेंशन और आसपास के क्षेत्रों में निकलने से पहले यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखकर यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई है।

संपादकीय

त्योहारों पर उमड़ती प्रवासियों की भीड़

औद्योगिक नगरी सूरत में रोजगार के लिए उत्तर भारत और राजस्थान के लाखों लोग बसे हैं। कपड़ा, हीरा और निर्माण कारोबार में काम करने वाले परिवारों के लिए दीपावली और छठ पूजा अपनी मिट्टी और परिवार से जुड़ने का अवसर हैं। नवरात्रि से ही गांव लौटने का सिलसिला शुरू हो जाता है। त्योहारों के आसपास उत्तर भारत जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों का दबाव बढ़ जाता है। इस वर्ष उधना स्टेशन पर उमड़ी भीड़ ने रेल सेवाओं और यात्रियों की जरूरत के बीच का अंतर फिर सामने रख दिया। शनिवार देर शाम स्टेशन पर भीड़ बढ़ने लगी। स्थिति संभालने के लिए मंडल रेल प्रबंधक सहित वरिष्ठ अधिकारी रात में पहुंचे। रेलवे, रेलवे सुरक्षा बल तथा राजकीय रेलवे पुलिस के जवानों ने यात्रियों को कतारों में लगवाया। करीब 40 करोड़ रुपये की लागत से 13 हजार वर्गमीटर में बने यात्री होल्डिंग एरिया को भी खोल दिया गया। बैरिकेडिंग कर प्रवेश की व्यवस्था की गई। भीड़ का दबाव इतना था कि कुछ समय बाद फिर कतारें बनवानी पड़ीं। यात्रियों की सुविधा के लिए उधना से छह अनारक्षित विशेष ट्रेनें चलाई गईं। इनके साथ तीन नियमित ट्रेनों से भी यात्रियों को रवाना किया गया। तड़के करीब 3.30 बजे अतिरिक्त विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इन सेवाओं से 25 हजार से अधिक यात्री रवाना हुए। यह संख्या बताती है कि त्योहारों में सूरत से घर जाने वालों की जरूरत कितनी बड़ी है। अतिरिक्त ट्रेनों से राहत मिली, लेकिन हर साल लौटने वाली भीड़ के लिए स्थायी रेल योजना जरूरी है।



उधना-जयनगर सहित उत्तर भारत की ट्रेनों में जगह की कमी से यात्रियों को परेशानी हुई। कई परिवारों ने भीड़ देखकर ट्रेन में चढ़ने के बजाय प्लेटफॉर्म पर इंतजार किया। बच्चों और सामान के साथ सफर करने वालों के लिए स्थिति कठिन रही। जयनगर, मुगलसराय और अन्य गंतव्यों के यात्रियों को जगह पाने के लिए जूझना पड़ा। विशेष ट्रेनें तत्काल राहत देती हैं, लेकिन पर्याप्त डिब्बे और नियमित सेवाएं उपलब्ध कराना भी जरूरी है।

होल्डिंग एरिया का निर्माण और उसका उपयोग स्वागतयोग्य कदम है। अब यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश से पहले कतारबद्ध करने की सुविधा बनी है। पत्रिका ने पहले भी यात्रियों की संख्या और उपलब्ध व्यवस्था के अंतर को उजागर किया था। इसके बाद रेलवे ने सुधार के निर्देश दिए। समस्याओं को सामने लाने से बदलाव संभव है। हालांकि स्टेशन परिसर व्यवस्थित करना ही पर्याप्त नहीं। मूल समाधान पर्याप्त ट्रेनें, अतिरिक्त कोच और समयबद्ध संचालन है। इस समस्या का अहम पक्ष राजस्थान के प्रवासी यात्रियों से जुड़ा है। सूरत, मुंबई और गुजरात के अन्य शहरों में मेवाड़ सहित राजस्थान के लाखों लोग रहते हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जाने वालों को कई बार सीधी रेल सुविधा नहीं मिलती। उन्हें दूसरे शहरों में उतरकर बस या निजी वाहन से यात्रा करनी पड़ती है।

आखिर कब प्रदूषण मुक्त होगी देश की राजधानी ?



महेन्द्र तिवारी
साहित्यकार एवं लेखक
पूर्व वायुसैनिक, नई दिल्ली

दिल्ली में दिवाली की आहट के साथ ही एक बार फिर प्रदूषण का संकट गहराने लगा है। त्योहार की तैयारियों के बीच राजधानी की हवा इतनी जहरीली होती जा रही है कि लोगों के लिए खुले में सांस लेना भी कठिन हो गया है। सुबह की सैर करने वाले लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। सड़कों, इमारतों और पेड़ों पर धुंध की मोटी परत दिखाई देने लगी है। आंखों में जलन, गले में खराश, खांसी और सांस लेने में परेशानी जैसी शिकायतें बढ़ रही हैं। यह स्थिति केवल पर्यावरण से जुड़ी समस्या नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर प्रश्न है।

भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान की वायु गुणवत्ता संबंधी निगरानी के अनुसार, दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार पहुंच गया। जहांगीरपुरी में यह 440, पंजाबी बाग में 436 और रोहिणी में 425 दर्ज किया गया। कुछ अन्य क्षेत्रों में भी स्थिति बेहद चिंताजनक रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, 3 नवंबर को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 350 तक पहुंच गया था। यह इस वर्ष फरवरी के बाद सबसे खराब स्थिति बताई गई। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि राजधानी की हवा अब सामान्य जनजीवन के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है।

प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 2 नवंबर को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्रमिक प्रतिक्रिया कार्ययोजना के दूसरे चरण को लागू कर दिया। इसके अंतर्गत सड़कों की नियमित यांत्रिक सफाई, धूल दबाने के लिए पानी का छिड़काव, निर्माण स्थलों पर कड़ी निगरानी और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नियंत्रण जैसे उपाय किए जा रहे हैं। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाने और यातायात के दबाव वाले स्थानों पर निगरानी बढ़ाने जैसे कदम भी उठाए गए हैं। हालांकि सवाल यह है कि क्या ये उपाय राजधानी को प्रदूषण से वास्तविक राहत दिला पाएंगे या फिर हर वर्ष की तरह कुछ दिनों की सख्ती के बाद स्थिति पहले जैसी हो जाएगी?

दिल्ली के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण किसी एक गतिविधि को नहीं माना जा सकता। इसके पीछे कई कारक एक साथ काम करते हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक इकाइयों का उत्सर्जन, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, सड़कों पर जमा मिट्टी, कूड़ा जलाना और आसपास के राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं वायु को प्रदूषित करती हैं। इसके अतिरिक्त मौसम में बदलाव भी इस समस्या को गंभीर बना देता है। तापमान में गिरावट, हवा की कम गति और वातावरण में नमी के कारण प्रदूषक कण ऊपर नहीं उठ पाते। वे धरती के निकट ही जमा होते रहते हैं। परिणामस्वरूप धुंध की मोटी परत बन जाती है और सांस के साथ सूक्ष्म प्रदूषक कण शरीर के भीतर पहुंचने लगते हैं।

हर वर्ष धान की कटाई के बाद पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में फसल अवशेष जलाने की घटनाएं सामने आती हैं। इस वर्ष भी इन घटनाओं में वृद्धि की खबरें हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उपग्रह आंकड़ों के अनुसार, 3 नवंबर को छह राज्यों में फसल अवशेष जलाने की 798 घटनाएं दर्ज की गईं। हालांकि दिल्ली के प्रदूषण के लिए केवल पराली को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। राजधानी के भीतर मौजूद प्रदूषण के स्रोत भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जब स्थानीय प्रदूषण और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां एक साथ मिलती हैं, तब समस्या और विकराल हो जाती है। इसलिए राज्यों के बीच आरोप-प्रत्यारोप के बजाय साझा समाधान की आवश्यकता है।

दिवाली के अवसर पर पटाखों का उपयोग इस समस्या को और बढ़ा सकता है। आतिशबाजी से निकलने वाला धुआं और सूक्ष्म कण पहले से प्रदूषित वातावरण में अतिरिक्त विषाक्तता पैदा करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रमाणित हरित पटाखों के सीमित उपयोग की अनुमति दी है। न्यायालय के निर्देश के अनुसार, 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे तथा रात 8 से 10 बजे तक ही इन्हें जलाया जा सकेगा। इनकी बिक्री 4 से 6 नवंबर तक निर्धारित अधिकृत स्थानों पर होगी। अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों, शिक्षण संस्थानों और घोषित शांत क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर रोक रहेगी। 9 नवंबर से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध फिर लागू हो जाएगा।

हरित पटाखों को पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाने वाला विकल्प माना जाता है। इनका निर्माण वैज्ञानिक मानकों और निर्धारित प्रमाणन के अनुसार किया जाता है। इनके पैकेट पर पहचान के लिए विशेष संकेत और क्यूआर कोड होना आवश्यक है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि हरित पटाखे प्रदूषण रहित नहीं होते। उनसे भी धुआं, ध्वनि और हानिकारक कण निकलते हैं। यदि बड़ी संख्या में लोग निर्धारित समय से अधिक देर तक आतिशबाजी करते हैं तो प्रदूषण कम करने का उद्देश्य विफल हो सकता है। इसलिए न्यायालय के निर्देशों का पालन केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है।

प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से सांस तथा हृदय संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों पर पड़ता है। छोटे बच्चों के फेफड़े विकास की अवस्था में होते हैं। ऐसे में जहरीली हवा उनके स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकती है। बुजुर्गों के लिए भी प्रदूषित वातावरण गंभीर खतरा पैदा करता है। स्वस्थ व्यक्ति भी लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से सांस संबंधी परेशानियों का शिकार हो सकता है। इस स्थिति में विद्यालयों, अस्पतालों और सार्वजनिक संस्थानों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। बच्चों को अनावश्यक रूप से खुले मैदानों में खेलने से रोकना, सुबह और शाम की बाहरी गतिविधियों को सीमित करना तथा चिकित्सकीय सलाह का पालन करना आवश्यक है।

प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार को तात्कालिक कदमों के साथ दीर्घकालिक योजना भी बनानी होगी। सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुविधाजनक और सुलभ बनाना इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि बसों और रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ेगी तथा उनकी सेवाएं नियमित होंगी तो निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो सकती है। पुराने और अधिक धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है। निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सड़कों की सफाई केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि वैज्ञानिक तरीके से नियमित रूप से की जानी चाहिए। औद्योगिक इकाइयों के उत्सर्जन की निगरानी भी लगातार होनी चाहिए। किसानों के सामने फसल अवशेषों के निपटारे की समस्या को समझे बिना पराली जलाने पर रोक लगाना पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें ऐसी मशीनों, तकनीकों और आर्थिक सहायता की जरूरत है, जिनसे खेतों में बचे अवशेषों का उपयोग किया जा सके। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। किसानों को दोषी ठहराने के बजाय उन्हें व्यवहारिक विकल्प उपलब्ध कराने होंगे। फसल अवशेषों से जैविक खाद, ऊर्जा और अन्य उपयोगी उत्पाद तैयार करने की व्यवस्था विकसित की जा सकती है। इससे पर्यावरण की रक्षा के साथ किसानों की आय बढ़ाने के अवसर भी पैदा होंगे। नागरिकों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। छोटी-छोटी सावधानियां सामूहिक रूप से बड़ा बदलाव ला सकती हैं। निजी वाहन के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, छोटी दूरी के लिए पैदल चलना, कूड़ा और पत्तियां नहीं जलाना, निर्माण सामग्री को ढककर रखना और अनावश्यक ऊर्जा खपत से बचना ऐसे कदम हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति अपना सकता है। त्योहार मनाने के लिए पटाखों को अनिवार्य मानने की सोच भी बदलनी होगी। दीपक, रंगोली, सामूहिक सांस्कृतिक आयोजन और परिवार के साथ उत्सव मनाने के अनेक विकल्प मौजूद हैं। त्योहार का वास्तविक आनंद तभी है, जब उसकी खुशियां किसी दूसरे के लिए बीमारी और परेशानी का कारण न बनें। दिल्ली की प्रदूषित हवा हमें विकास की दिशा और जीवन की गुणवत्ता पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करती है। ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और चमकते बाजार किसी शहर की सफलता के पर्याप्त प्रमाण नहीं हो सकते। किसी राजधानी की वास्तविक समृद्धि इस बात से भी तय होती है कि वहां रहने वाले नागरिक कितनी स्वच्छ हवा में सांस लेते हैं। हर वर्ष सर्दियों के आरंभ में प्रदूषण का बढ़ना और फिर अस्थायी उपायों से उसे नियंत्रित करने का प्रयास हमारी नीतियों की कमजोरियों को उजागर करता है। अब समय आ गया है कि प्रदूषण को मौसमी संकट मानने के बजाय स्थायी सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय चुनौती के रूप में देखा जाए। दिवाली प्रकाश, उल्लास और नई आशाओं का त्योहार है। इसकी चमक धुएं और धुंध में खोनी नहीं चाहिए। सरकार, प्रशासन, उद्योग, किसान और आम नागरिक, सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अदालत के आदेशों का पालन और प्रदूषण नियंत्रण के उपाय तभी सफल होंगे, जब उनके साथ जनभागीदारी भी जुड़ी होगी। हमें ऐसी दिवाली मनाने का संकल्प लेना चाहिए, जिसमें घरों और गलियों में दीप जलें, चेहरों पर मुस्कान हो और हवा में सांस लेने का भरोसा बना रहे। आखिर स्वच्छ हवा किसी एक मौसम या त्योहार की जरूरत नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का बुनियादी अधिकार है।

संकट पानी का नहीं, उसके उचित प्रबंधन का है

मन्जू
लूणकरणसर, राजस्थान

राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में गर्मी का मौसम केवल तापमान बढ़ने का समय नहीं होता, बल्कि यह पानी की उपलब्धता और उसके प्रबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा भी होती है। जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती है, गांवों में कुओं, तालाबों और जलाशयों का पानी कम होने लगता है। कई जगह हैंडपंप और नलकूप पर्याप्त पानी नहीं दे पाते। इसका असर केवल लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर नहीं पड़ता, बल्कि पशुपालन और खेती भी इससे प्रभावित होते हैं। राजस्थान के लूणकरणसर जैसे शुष्क क्षेत्रों में पानी की कमी का अर्थ है कि ग्रामीण परिवारों को पीने के पानी से लेकर पशुओं के लिए चारा उगाने तक, हर स्तर पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

यहां यह समझना जरूरी है कि राजस्थान में वर्षा का वितरण असमान है। राज्य के पश्चिमी हिस्से में बारिश कम और अनिश्चित होती है। कई बार अच्छी बारिश के बावजूद पानी का बड़ा हिस्सा बहकर निकल जाता है या तेज गर्मी के कारण जल्दी वाष्पित हो जाता है। दूसरी ओर, भूजल पर लगातार बढ़ती निर्भरता ने स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बनाया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के वर्ष 2024 के आकलन के अनुसार, राजस्थान में सालाना भूजल दोहन की दर 148.77 प्रतिशत थी। राज्य की 302 आकलन इकाइयों में से 216 को अत्यधिक दोहन की श्रेणी में रखा गया था। इसका अर्थ है कि जितना भूजल प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो रहा है, उससे कहीं अधिक निकाला जा रहा है।इस दिशा में सबसे जरूरी कदम वर्षा जल का संचयन है। राजस्थान में पारंपरिक रूप से पानी जमा करने के कई तरीके प्रचलित रहे हैं। टांका, जोहड़, नाड़ी, खड़ीन, बावड़ी और कुंड जैसी व्यवस्थाएं स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों और कम वर्षा को ध्यान में रखकर विकसित की गई थीं। इन परंपरागत संरचनाओं को आधुनिक तकनीक के साथ फिर से मजबूत करने की जरूरत है। गांवों में घरों की छतों से बारिश का पानी पाइप के माध्यम से टांकों और भूमिगत टंकियों तक पहुंचाया जा सकता है। पंचायत स्तर पर तालाबों की सफाई, गहरीकरण और उनके आसपास जलग्रहण क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए। खेतों में छोटे जलाशय और फार्म पॉन्ड बनाकर बारिश के पानी को जमा किया जा सकता है। इससे एक ओर भूजल का पुनर्भरण होगा, वहीं दूसरी ओर गर्मियों में पशुओं और खेती के लिए पानी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

राजस्थान सरकार ने जल संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 शुरू किया है। फरवरी 2024 में शुरू की गई इस योजना के तहत अगले चार वर्षों में राज्य के 20 हजार गांवों में पांच लाख जल संग्रहण और संरक्षण संरचनाएं बनाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार की 2024-25 की बजट घोषणा में इस अभियान के लिए लगभग 11,200 करोड़ रुपये का प्रावधान बताया गया था।

पेयजल उपलब्धता के लिए केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना भी महत्वपूर्ण है। जुलाई 2026 में प्रकाशित जानकारी के अनुसार राजस्थान के लगभग 1.07 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से करीब 63.64 लाख परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया था। यह कुल ग्रामीण परिवारों का लगभग 59.11 प्रतिशत था। राज्य के सामने शेष परिवारों तक कनेक्शन पहुंचाने के साथ जल स्रोतों को टिकाऊ बनाए रखने की चुनौती भी है।

खेती में पानी की खपत कम करना भी जल संकट के स्थायी समाधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राजस्थान में बड़ी संख्या में किसान सिंचाई के लिए भूजल पर निर्भर हैं। पारंपरिक तरीके से खेतों में पानी भरकर सिंचाई करने से काफी पानी व्यर्थ चला जाता है। इसके स्थान पर ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना चाहिए। राजस्थान सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर लगाने के लिए अनुदान दे रही है। राज्य के आर्थिक समीक्षा दस्तावेज 2025-26 के अनुसार सामान्य किसानों को 70 प्रतिशत और अनुसूचित जाति-जनजाति, महिला, छोटे एवं सीमांत किसानों को 75 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है। इसके बावजूद छोटे किसानों तक इन तकनीकों की पहुंच बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए पंचायत स्तर पर प्रदर्शन खेत विकसित किए जा सकते हैं, जहां किसान इन प्रणालियों को देखकर और समझ कर अपना सकें। पानी की कमी से जूझ रहे दूसरे राज्यों और देशों के अनुभव भी राजस्थान के लिए उपयोगी हो सकते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का हिवरे बाजार गांव इसका एक अच्छा उदाहरण है। कभी पानी की गंभीर कमी से जूझने वाले इस गांव में ग्रामीणों ने जलग्रहण क्षेत्र का विकास, वर्षा जल संचयन, छोटे बांधों और मिट्टी-पानी संरक्षण के कार्यों को सामुदायिक भागीदारी से आगे बढ़ाया। लगभग 400 मिलीमीटर सालाना बारिश वाले इस गांव ने पांच वर्षों में अपनी जल उपलब्धता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार किया। इस बदलाव में सरकारी योजनाओं और पंचायत के संसाधनों के साथ ग्रामीणों की सामूहिक भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह उदाहरण बताता है कि कम बारिश वाले क्षेत्रों में भी सही योजना और सामुदायिक प्रयास से पानी की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। इसी तरह इजरायल ने सीमित जल संसाधनों के बावजूद कृषि क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई और शोधित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग को व्यापक स्तर पर अपनाया है। वहां शहरी क्षेत्रों से निकलने वाले गंदे पानी को शोधित करके खेती में इस्तेमाल किया जाता है। राजस्थान में भी शहरों और कस्बों के सीवेज को उचित तकनीक से साफ करके गैर-खाद्य फसलों, बागवानी और औद्योगिक जरूरतों के लिए इस्तेमाल करने की संभावनाएं विकसित की जा सकती हैं। इससे भूजल और मीठे पानी पर निर्भरता कम होगी। दरअसल, राजस्थान के गांवों में पानी की समस्या का समाधान केवल नए जल स्रोत बनाने में नहीं, बल्कि उपलब्ध पानी को बचाने, जमा करने और जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करने में छिपा है। यदि वर्षा जल संचयन, आधुनिक सिंचाई तकनीक, पारंपरिक जल संरचनाओं के पुनर्जीवन और सामुदायिक भागीदारी को एक साथ आगे बढ़ाया जाए तो स्थिति में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।

लिव इन रिलेशनशिप : मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियां और समाधान

-डॉ. मनोज कुमार तिवारी
वरिष्ठ परामर्शदाता
एआरटीसी, एसएस हॉस्पिटल,
आईएमएस, बीएचयू, वाराणसी

आधुनिक समाज में रिश्तों और पारिवारिक जीवन की अवधारणाओं में तेजी से बदलाव आ रहा है। इसी बदलाव के बीच लिव इन रिलेशनशिप भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक विषय बनकर उभरा है। यह ऐसी व्यवस्था है, जिसमें दो वयस्क बिना औपचारिक विवाह के एक साथ रहते हैं और आपसी सहमति से घरेलू तथा भावनात्मक जीवन साझा करते हैं।

इस संबंध में दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे की आदतों, स्वभाव, विचारों और जीवनशैली को करीब से समझने का अवसर मिलता है। हालांकि, इस व्यवस्था के सकारात्मक पहलुओं के साथ सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। रिश्ते की गुणवत्ता, आपसी सम्मान, विश्वास और भविष्य को लेकर स्पष्टता इसके मानसिक प्रभाव को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रमुख विशेषताएं और कानूनी स्थिति

लिव इन रिलेशनशिप का आधार दोनों वयस्क व्यक्तियों की स्वतंत्र इच्छा और पारस्परिक सहमति है। इसमें जोड़े विवाह के औपचारिक बंधन के बिना साथ रहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों, आर्थिक व्यवस्था तथा व्यक्तिगत जीवन से जुड़े निर्णय आपसी समझ के आधार पर लेते हैं। हर प्रकार का साथ रहना लिव इन रिलेशनशिप नहीं माना जाता। संबंध की प्रकृति, साझा घरेलू जीवन और पारस्परिक प्रतिबद्धता जैसे पहलुओं का महत्व होता है।

भारत में लिव इन रिलेशनशिप को नियंत्रित करने वाला कोई एक व्यापक विशेष अधिनियम नहीं है। हालांकि, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आधार पर बालिग व्यक्तियों को अपनी पसंद से साथ रहने की स्वतंत्रता प्राप्त है, बशर्ते उनका संबंध कानून के विरुद्ध न हो।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 2(द्ध) में विवाह की प्रकृति वाले संबंधों को शामिल किया गया है। परिस्थितियों के अनुसार ऐसे संबंधों में रहने वाली महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण और अन्य कानूनी राहत मिल सकती है। हालांकि, प्रत्येक लिव इन संबंध को स्वतः विवाह के समान कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं होता। भरण पोषण, संपत्ति और अन्य अधिकारों का निर्धारण लागू कानूनों तथा संबंध की वास्तविक प्रकृति के आधार पर किया जाता है।

लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चों के अधिकारों को भी कानून संरक्षण प्रदान करता है। उनके भरण पोषण और उत्तराधिकार संबंधी अधिकार लागू कानूनों तथा न्यायिक निर्णयों के अनुसार निर्धारित होते हैं।

लिव इन रिलेशनशिप के सकारात्मक पहलू

लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहने से दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे की आदतों, स्वभाव और विचारों को समझने का अवसर मिल सकता है। इससे रिश्ते की वास्तविक परिस्थितियों को जानने और भविष्य के बारे में सोच समझकर निर्णय लेने में मदद मिल सकती है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। दोनों व्यक्ति अपनी शिक्षा, करियर और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए घरेलू जिम्मेदारियों को साझा कर सकते हैं। यदि रिश्ता सम्मान, विश्वास और सहयोग पर आधारित हो, तो यह भावनात्मक सहारा प्रदान कर सकता है और अकेलेपन की भावना को कम करने में मदद कर सकता है।

एक स्वस्थ संबंध में व्यक्ति को अपनापन, सुरक्षा और स्वीकार्यता का अनुभव होता है। इससे तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायता मिल सकती है। हालांकि, ये लाभ केवल साथ रहने से नहीं, बल्कि रिश्ते की गुणवत्ता और दोनों व्यक्तियों के व्यवहार पर निर्भर करते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव

लिव इन रिलेशनशिप में भावनात्मक सहयोग मिलने से व्यक्ति को मानसिक मजबूती मिल सकती है। कठिन परिस्थितियों में साथी का समर्थन तनाव को संभालने और समस्याओं का समाधान खोजने में सहायक हो सकता है।

आपसी समझ और खुला संवाद रिश्ते में अनावश्यक तनाव को कम कर सकते हैं। जब दोनों व्यक्ति अपनी भावनाओं, अपेक्षाओं और सीमाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, तो गलतफहमियों की संभावना कम हो सकती है।

सम्मानपूर्ण और सहयोगपूर्ण संबंध में भावनात्मक निकटता तथा अपनापन महसूस होता है। इससे मानसिक संतुष्टि बढ़ सकती है। इसके विपरीत, यदि संबंध में लगातार तनाव या असुरक्षा बनी रहे, तो साथ रहने के बावजूद मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है।

नकारात्मक प्रभाव और मानसिक चुनौतियां

भारतीय समाज के कई हिस्सों में लिव इन रिलेशनशिप को अभी भी पूरी सामाजिक स्वीकार्यता प्राप्त नहीं है। ऐसे संबंधों में रहने वाले व्यक्तियों को परिवार की नाराजगी, सामाजिक आलोचना, ताने और अलगाव का सामना करना पड़ सकता है। लगातार सामाजिक दबाव मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद का कारण बन सकता है।

रिश्ते के भविष्य को लेकर अनिश्चितता भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। यदि दोनों व्यक्तियों की अपेक्षाएं अलग हों या प्रतिबद्धता को लेकर स्पष्टता न हो, तो असुरक्षा और भावनात्मक असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। रिश्ते में लगातार विवाद, अविश्वास, संवाद की कमी या भावनात्मक शोषण होने पर व्यक्ति का आत्मसम्मान प्रभावित हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में चिंता, उदासी और मानसिक थकान बढ़ सकती है।

यदि संबंध में बच्चे हों, तो उनके भावनात्मक विकास और सामाजिक वातावरण पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। बच्चों की भलाई उनकी पारिवारिक स्थिति से अधिक प्यार, सुरक्षा, स्थिरता और सहयोग पर निर्भर करती है।

संबंध टूटने का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव

लिव इन रिलेशनशिप का टूटना कई व्यक्तियों के लिए गहरे भावनात्मक आघात का कारण बन सकता है। लंबे समय तक साथ रहने के बाद अचानक अलगाव होने से अकेलापन, निराशा और भविष्य को लेकर चिंता महसूस हो सकती है।

संबंध टूटने के बाद तनाव और अवसाद के लक्षण उभर सकते हैं। व्यक्ति को नींद न आने, भूख में बदलाव, अत्यधिक सोचने और दैनिक कार्यों में रुचि कम होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मानसिक उलझन के कारण पढ़ाई, नौकरी और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो सकता है।

लंबे समय तक किसी रिश्ते में रहने के दौरान व्यक्ति की पहचान और दिनचर्या उस संबंध से जुड़ सकती है। अलगाव के बाद स्वयं को नए सिरे से समझने और स्वतंत्र जीवन में तालमेल बैठाने में समय लग सकता है।

कुछ लोग भावनात्मक दर्द से बचने के लिए शराब, धूम्रपान या अन्य नशीले पदार्थों का सहारा लेने लगते हैं। इससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल और समाधान

रिश्ते में तनाव या अलगाव की स्थिति में अपनी भावनाओं को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। उदासी, गुस्सा, निराशा और अकेलेपन का अनुभव स्वाभाविक हो सकता है। भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना चाहिए। डायरी लिखना, नियमित व्यायाम और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेना सहायक हो सकता है। परिवार, भरोसेमंद मित्रों और करीबी लोगों से बातचीत करने से भावनात्मक बोझ कम हो सकता है। नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और शारीरिक गतिविधि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।

विश्व सुनामी जागरूकता दिवस : प्रकृति के संकेत पहचानें, सतर्कता से जीवन बचाएँ

- सुरेश सिंह बैस 'शाश्वत'

प्रकृति जीवनदायिनी है, लेकिन जब उसका संतुलन बिगड़ता है या समुद्र के भीतर भूगर्भीय हलचल होती है, तो वही प्रकृति विनाशकारी रूप भी धारण कर सकती है। सुनामी ऐसी ही एक भयावह प्राकृतिक आपदा है, जिसकी विशाल लहरें कुछ ही समय में तटीय बस्तियों, घरों, सड़कों और जनजीवन को तबाह कर सकती हैं। इस आपदा की भयावहता को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय है वैज्ञानिक चेतावनी, समय पर सुरक्षित स्थान तक पहुँचना और जनसामान्य में जागरूकता लाना।

इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2015 में इस दिवस की घोषणा की थी। इस तारीख का संबंध जापान की एक ऐतिहासिक घटना से है, जिसमें 1854 में एक ग्रामीण ने सुनामी के खतरे का संकेत देने के लिए धान की पूलियों में आग लगाई, जिससे गाँव के लोगों को सतर्क होकर सुरक्षित स्थान की ओर जाने में सहायता मिली। सुनामी समुद्र में उत्पन्न होने वाली शक्तिशाली लहरों की शृंखला है। इसका प्रमुख कारण समुद्र तल के नीचे आने वाला भूकंप हो सकता है। इसके अतिरिक्त समुद्र के भीतर भूस्खलन और ज्वालामुखीय गतिविधियाँ भी सुनामी पैदा कर सकती हैं।

सामान्य समुद्री लहरों के विपरीत, सुनामी की लहरें अत्यधिक ऊर्जा लेकर लंबी दूरी तय कर सकती हैं। तट के निकट पहुँचने पर समुद्र की गहराई कम होने के कारण इनका व्यवहार बदल सकता है और जलराशि तेजी से भूमि की ओर बढ़ सकती है। परिणामस्वरूप जनहानि, संपत्ति का विनाश, पेयजल स्रोतों का दूषित होना और आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में आई विनाशकारी सुनामी ने भारत सहित अनेक देशों को गहरे घाव दिए थे। इस त्रासदी ने स्पष्ट किया कि समुद्र तटों पर रहने वाले समुदायों के लिए पूर्व चेतावनी, प्रशिक्षित आपदा प्रबंधन और सामुदायिक तैयारी कितनी आवश्यक है।

विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2026 का विषय है - Be Tsunami Ready Resilience Starts With You ', अर्थात सुनामी के लिए तैयार रहें; सुदृढ़ता की शुरुआत स्वयं से होती है। यह संदेश बताता है कि केवल सरकारी चेतावनी प्रणाली पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को खतर

संक्षिप्त समाचार

एएसआर फाउण्डेशन का सहयोग अभियान 10 नवंबर से होगा शुरू

अनप्लग इंडिया

गुडगांव : सामाजिक संस्था ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन (एएसआर फाउण्डेशन) द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष आगामी 10 नवम्बर से वार्षिक शीतकालीन सहयोग अभियान का आयोजन किया जाएगा। संस्था के अध्यक्ष एमपी शर्मा का कहना है कि संस्था पिछले 5 वर्षों से शीतकालीन दिनों में संस्था जरुरतमंदों परिवारों को कंबल, शॉल, स्वेटर, जैकेट, मोजे, टोपी, खाद्य सामग्री तथा जरुरतमंद छात्रों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराती आ रही है। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों व बुजुर्गों के लिए कृत्रिम उपकरण तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आगामी 10 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक यह अभियान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया जाएगा। उन्होंने आर्थिक रुप से संपन्न लोगों से आग्रह किया है कि वे जरुरतमंदों की सहायता के लिए आगे आकर संस्था का सहयोग करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सहायता उपलब्ध कराई जा सके। संस्था ने सभी नागरिकों से इस अभियान में स्वयंसेवक बनकर जरूरतमंदों के चेहरों पर मुस्कान लाने की अपील की है। अभियान की तैयारियों में संस्था के एमपी नागर, बनजीत सिंह, वीएस बोकन, खतीजा आदि जुटे हुए हैं।

99 प्रतिशत हार्ट ब्लॉकेज का हवाला देकर जन जागरण मंच ने राष्ट्रपति से गुहार

अनप्लग इंडिया

गुडगांव : यौन उत्पीड़न मामले में सजा काट रहे आसाराम बापू की बिगड़ती सेहत का हवाला देते हुए सामाजिक संस्था जन जागरण मंच ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र भेजकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। संस्था ने पत्र में दावा किया है कि 90 वर्षीय आसाराम बापू की हृदय धमनियों में लगभग 99 प्रतिशत ब्लॉकेज है और उन्हें पूर्व में कई बार हार्ट अटैक आ चुके हैं। संस्था ने राष्ट्रपति से उन्हें जोधपुर स्थित आरोग्यधाम आयुर्वेदिक अस्पताल में स्थानांतरित करने और 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में रखने का आग्रह किया है। संस्था के अध्यक्ष हरी शंकर कुमार का कहना है कि पत्र में आसाराम बापू के निजी चिकित्सक डॉ. सचित भोला के आरोपों का भी उल्लेख किया गया है। आरोप है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद जेल प्रशासन उनके स्वास्थ्य परीक्षण और चिकित्सा देखभाल में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। जन जागरण मंच ने इन आरोपों की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कराने और डॉक्टर को बिना किसी रुकावट के चिकित्सा परीक्षण की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि जेल में निरुद्ध होने के बावजूद हर व्यक्ति को जीवन, स्वास्थ्य और मानवीय गरिमा का अधिकार प्राप्त है। पत्र में कहा गया है कि यह मांग न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप के उद्देश्य से नहीं, बल्कि एक अति-वृद्ध और गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को उचित चिकित्सा सुविधा और मानवीय देखभाल उपलब्ध कराने के लिए की गई है। कुमार ने राष्ट्रपति से राजस्थान सरकार, गृह विभाग और जेल प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मंगवाकर आवश्यक निर्देश जारी करने की अपील की है।

मोटरस्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले प्रतीक दलाल को विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने किया सम्मानित

अनप्लग इंडिया

चंडीगढ़। हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने बुधवार को अपने चैंबर में मोटरस्पोर्ट्स खिलाड़ी प्रतीक दलाल को सम्मानित किया। प्रतीक ने एशिया पैसिफिक मोटरस्पोर्ट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इस प्रतियोगिता आयोजन गत 23 से 25 अक्तूबर तक थाईलैंड के पटाया शहर में हुआ था। हरियाणा के बहादुरगढ़ निवासी प्रतीक दलाल ने 53.409 सेकंड का समय लेकर थाईलैंड के अपिलुक लोटागा (53.765 सेकंड) को 0.356 सेकंड के अंतर से हराया। प्रतियोगिता का आयोजन एफआईए के तत्वावधान में रॉयल ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ थाईलैंड की ओर से किया गया। इसमें 16 देशों के 36 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि प्रतीक दलाल ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा, कौशल, साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए एशिया पैसिफिक मोटरस्पोर्ट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। मोटरस्पोर्ट्स जैसे चुनौतीपूर्ण खेल में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करना खिलाड़ी के अनुशासन, निरंतर अभ्यास और कठिन परिश्रम का प्रमाण है। प्रतीक ने बेहद मामूली अंतर से अपने प्रतिद्वंद्वी को पीछे छोड़कर यह साबित किया है कि बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए आत्मविश्वास, एकाग्रता और अंतिम क्षण तक बेहतर प्रदर्शन करने का जज्बा जरूरी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की पहचान खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की भूमि के रूप में रही है। प्रदेश के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। अब मोटरस्पोर्ट्स जैसे अपेक्षाकृत अलग और चुनौतीपूर्ण खेलों में भी हरियाणा के युवा अपनी पहचान बना रहे हैं, जो प्रदेश की खेल प्रतिभाओं के विविध आयामों को दर्शाता है। प्रतीक दलाल की यह उपलब्धि युवाओं को नए खेलों में आगे बढ़ने और अपनी रुचि एवं प्रतिभा के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करेगी।

विधान सभा अध्यक्ष ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रतीक दलाल भविष्य में भी इसी लगन और समर्पण के साथ देश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धियां हासिल करेंगे। उन्होंने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि ऐसी सफलताएं देश में मोटरस्पोर्ट्स को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ इस खेल के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होंगी।

प्रतीक ने बीटेक किया है और फिलहाल वे अपना बिजनेस करते हैं। उन्होंने अपने खेल की शुरुआत वर्ष 2010 में कोयंबटूर में आयोजित वोक्सवैगन पोलो कप इंडिया से की थी। इस अवसर पर प्रतीक के पिता कुलदीप सिंह दलाल, उनके ससुर इकबाल सिंह जून भी मौजूद रहे।

पंचकूला में सहपाठी की पिटाई से घायल 6 वर्ष की बच्ची पीजीआईएमईआर से डिस्चार्ज, परिवार ने ली राहत की सांस

अनप्लग इंडिया

चंडीगढ़। हरियाणा के पंचकूला में एक स्कूली साथी द्वारा बेरहमी से पीटे जाने के बाद 28 अक्टूबर को चंडीगढ़ के पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर) में भर्ती कराई गई छह वर्ष की बच्ची को बुधवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। बच्ची को बेहतर इलाज मिलने से उसके परिवार और आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली है। पंचकूला के सेक्टर 20 स्थित एक स्कूल में विशेष जरूरतों वाली एक बच्ची के साथ तीसरी कक्षा के एक छात्र ने बेरहमी से मारपीट की। छात्र ने कई बार दीवार पर बच्ची का सिर दे मारा और जब वह खून से लथपथ होकर क्लासरूम के फर्श पर बेहोश पड़ी थी, तब भी उस पर ईंट से हमला किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने कहा था कि वह बच्ची के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी और राज्य भर के स्कूलों में सुरक्षा का व्यापक ऑडिट कराएगी।

हालांकि, संवेदनशील और समान स्वास्थ्य सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए पीजीआईएमईआर ने बच्ची के परिवार पर कोई आर्थिक बोझ डाले बिना उसका इलाज किया। संस्थान ने उसके निजी कमरे का खर्च भी उठाया, ताकि इस मुश्किल समय में परिवार पूरी तरह से बच्ची के ठीक होने पर ध्यान दे सके।

पीजीआईएमईआर के निदेशक प्रो. विवेक लाल, जो अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान बच्ची का हाल-चाल जानने गए थे, ने उसके सफलतापूर्वक डिस्चार्ज होने पर खुशी और राहत जताई।

उन्होंने कहा, 'इस बच्ची का सुरक्षित डिस्चार्ज होना हम सभी के लिए बहुत राहत और खुशी की बात है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने हमें अंदर तक झकझोर दिया था। हमारी पहली प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना था कि उसे पूरी संवेदना, आराम और भरोसे के माहौल में बेहतरीन चिकित्सा देखभाल मिले। ' 'मैं बच्ची के इलाज और ठीक होने की प्रक्रिया के दौरान हमारे डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों द्वारा दिखाए गए समर्पण और संवेदनशीलता की दिल से सराहना करता हूं। '

गलत प्रॉपर्टी आईडी बनाने पर दो अफसरों की 3 माह तक कटेगी 50 प्रतिशत सैलरी, सीएम ने दिए निर्देश

अनप्लग इंडिया

गुरुग्राम। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहाकि प्रदेश के सरकारी स्कूलों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत दिसंबर 2027 के अंत तक 400 से अधिक सरकारी स्कूलों को नए भवन उपलब्ध करवाए जाएंगे। सरकार का प्रयास है कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आधुनिक सुविधाएं मिलें।

मुख्यमंत्री ने यह जानकारी बुधवार को गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान एक स्कूल के भवन के जीर्णोद्धार से संबंधित शिकायत की सुनवाई करते हुए दी। बैठक में कुल 15 परिवाद सुनवाई के लिए रखे गए, जिनमें से मुख्यमंत्री ने 11 का मौके पर ही निपटारा किया, जबकि शेष 4 मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन मामलों में की गई कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करने को कहा। बैठक में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी की विधायक बिमला चौधरी, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर और गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा भी उपस्थित रहे।



मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना और उन्हें निर्धारित समय-सीमा में बेहतर, सुगम एवं गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करवाना सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। सरकार का संकल्प है कि प्रत्येक नागरिक की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उसका त्वरित एवं प्रभावी निवारण सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नगर परिषद पटौदी-जटौली मंडी क्षेत्र से संबंधित एक शिकायत की सुनवाई करते हुए गलत तरीके से प्रॉपर्टी आईडी बनाने तथा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं की अनदेखी के मामले को गंभीरता से लिया। जांच में सामने आया कि तत्कालीन बिल्डिंग इंस्पेक्टर और म्युनिसिपल इंजीनियर ने सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बगैर प्रॉपर्टी आईडी बनाई थीं।

मुख्यमंत्री ने ड्यूटी में गंभीर लापरवाही बरतने पर दोनों अधिकारियों की तीन माह तक 50 प्रतिशत सैलरी काटने, उनके चार्जशीट करने तथा हरियाणा के एनसीआर जिलों से बाहर तबादला करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यों में लापरवाही और नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आमजन के हितों से जुड़े मामलों में अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों की स्वच्छता एवं रखरखाव से जुड़ी शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए। उन्होंने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के माध्यम से प्रत्येक जोन में तीन सदस्यीय कमेटी गठित करने को कहा, जिसमें एक सरकारी अधिकारी भी शामिल होगा। ये कमेटियां गुरुग्राम नगर निगम के छह तथा मानेसर नगर निगम के दो जोन में सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति और साफ-सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में सार्वजनिक शौचालयों के बेहतर रखरखाव और नियमित स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक में एक नागरिक की शिकायत पर सुनवाई करते हुए नगर निगम गुरुग्राम के पटवारी द्वारा गलत व्यवहार किए जाने के मामले को गंभीरता से लिया। शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार की बात सामने आने पर मुख्यमंत्री ने संबंधित पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की जिम्मेदारी है। सरकारी कार्यालयों में अपने कार्यों के लिए आने वाले लोगों के साथ दुर्व्यवहार या उनकी शिकायतों की अनदेखी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने सड़क के जीर्णोद्धार कार्य में लापरवाही बरतने और निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य नहीं किए जाने से संबंधित शिकायत पर सुनवाई करते हुए मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के संबंधित कार्यकारी अभियंता की एक माह की सैलरी काटने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण एवं जीर्णोद्धार से जुड़े कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विकास कार्यों की नियमित निगरानी करें।

इस अवसर पर शहरी विकास विभाग के प्रधान सलाहकार डी. एस ढेसी, जीएमडीए के सीईओ पी.सी मीणा, सीपी शिवास कविराज, डीसी उत्तम सिंह, एचएसवीपी की प्रशासक वैशाली सिंह, मानेसर के निगम आयुक्त प्रदीप सिंह, मुख्यमंत्री के ओएसडी तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अतिरिक्त निदेशक विवेक कालिया, एडीसी सोनू भट्ट, सीटीएम ज्योति नागपाल, भाजपा के गुरुग्राम महानगर के जिला अध्यक्ष अजीत यादव सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

हरियाणा: दीपावली पर प्रदेश के अस्पताल अलर्ट मोड पर रहेंगे- आरती राव

अनप्लग इंडिया

चंडीगढ़ । हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने दीपावली पर्व के दौरान अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने और आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करने के लिए विशेष सलाह जारी की है। त्योहार के समय पटाखों और अन्य हादसों के कारण जलने और सांस संबंधी समस्याओं के मामलों में बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए उन्होंने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में बर्न-वार्ड अलग से तैयार रखने के निर्देश दिए हैं।

आपातकालीन केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में ब्रोंकोडायलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर और बर्न ट्रीटमेंट किट जैसी आवश्यक दवाओं व चिकित्सा आपूर्ति का पहले से ही प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा गया है। आतिशबाजी या किसी भी प्रकार दुर्घटना के शिकार लोगों का त्वरित इलाज संभव हो सके, इसके लिए सभी सरकारी अस्पतालों में 20 से अधिक बेड आरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। दीपावली के दिन सामान्य दिनों की तुलना में सड़क हादसों, झुलसने और आंखों की चोटों की घटनाओं में इजाफा होता है, जिसे देखते हुए इमरजेंसी विभाग के अलावा नेत्र रोग (ऑप्थैल्मोलॉजी), आर्थोपेडिक और सर्जरी विभागों में भी बेड सुरक्षित रखे जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिया है कि नेत्र रोग, आर्थोपेडिक और सर्जरी विशेषज्ञों को अलर्ट मोड और ऑन-कॉल ड्यूटी पर रखा जाए ताकि पीड़ितों को तुरंत और प्रभावी इलाज मिल सके।

दीपावली के दिन किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों के विशेषज्ञों को तैनात रहने का आदेश जारी किया गया है।



इसके अतिरिक्त बर्न मरीजों के लिए पर्याप्त संख्या में स्ट्रेचर, बेड, आई/वी स्टैंड, आई/वी सोलूशन्स और एंटीबायोटिक्स की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। दीपावली पर्व के दौरान चिकित्सा कर्मियों और विशेषज्ञों को शहर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी तथा आई और ईएनटी विशेषज्ञों की टीमें अस्पतालों में मौजूद रहेंगी। वहीं गंभीर मामलों की त्वरित देखभाल के लिए अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर और आईसीयू में भी विशेष रूप से बेड आरक्षित किए जाएंगे।

पदयात्रा की तैयारियों का महापौर ने लिया जायजा, सेक्टर-12 में किया स्थल निरीक्षण

अनप्लग इंडिया

करनाल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के करनाल आगमन पर आयोजित होने वाली 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा की तैयारियों को लेकर महापौर रेणु बाला गुप्ता लगातार सक्रिय हैं। आयोजन को सुव्यवस्थित और सफल बनाने के उद्देश्य से महापौर ने सेक्टर-12 स्थित पदयात्रा स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक मंगला, करनाल विधायक जगमोहन आनंद, जिला प्रभारी जवाहर यादव और रोहतक के महापौर राम अवतार के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर विभिन्न व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई और कार्यक्रम में पहुंचने वाले कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। महापौर ने व्यवस्थाओं में आपसी समन्वय और समयबद्ध तैयारी पर जोर देते हुए कहा कि इतने बड़े आयोजन में प्रत्येक छोटी-बड़ी व्यवस्था का दुरुस्त होना जरूरी है, ताकि कार्यक्रम में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को असुविधा न हो।

इस अवसर पर महापौर रेणु बाला गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का करनाल आगमन शहर के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी एवं समर्पण के साथ अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि संगठन की एकजुटता, कार्यकर्ताओं का उत्साह और जनसहभागिता किसी भी बड़े आयोजन की सफलता के महत्वपूर्ण आधार हैं।

महापौर ने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयासों और बेहतर तालमेल से इस आयोजन को सुव्यवस्थित एवं यादगार बनाया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान



किया कि वे पूरी सक्रियता के साथ तैयारियों में जुटें और कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करें। महापौर ने विश्वास व्यक्त किया कि करनाल के कार्यकर्ताओं का उत्साह और सामूहिक प्रयास इस आयोजन को विशेष स्वरूप प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि करनाल इस महत्वपूर्ण आयोजन के स्वागत और तैयारियों के लिए पूरी तरह जुटा हुआ है।

दो साल का हिसाब दे भाजपा सरकार, 20 चुनावी वादों पर जारी करे श्वेतपत्र : कुमारी सैलजा

अनप्लग इंडिया

चंडीगढ़। हरियाणा की भाजपा सरकार के दो साल के कार्यकाल को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं सिरसा सांसद कुमारी सैलजा ने सरकार से विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए 20 प्रमुख वादों पर जवाब मांगते हुए वादावार श्वेतपत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने महिलाओं, युवाओं, किसानों, कर्मचारियों और गरीब परिवारों से बड़े-बड़े वादे किए थे। अब सरकार को बताना चाहिए कि इनमें से कितने वादे पूरे हुए और कितने अब भी अधूरे हैं। कुमारी सैलजा ने कहा कि लोकतंत्र में जनता के प्रति जवाबदेही सरकार का दायित्व है। दो साल बीतने के बाद केवल घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, बल्कि सरकार को अपने वादों की वास्तविक स्थिति और उपलब्धियों का हिसाब देना होगा। 2100 रुपए महिला सम्मान राशि पर मांगा जवाब

सांसद ने कहा कि भाजपा ने महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपए देने का वादा किया था। सरकार बताए कि वर्तमान में कितनी महिलाओं को यह राशि मिल रही है, कितनी महिलाएं इसके लिए पात्र हैं और शेष पात्र महिलाओं को कब तक इसका लाभ मिलेगा। इसी तरह प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने की घोषणा पर भी सरकार को बताना चाहिए कि कितने परिवारों को वास्तविक स्वास्थ्य कवरेज मिला और कितने मरीज लाभान्वित हुए। युवाओं के मुद्दे पर सैलजा ने कहा कि भाजपा ने दो लाख पक्की सरकारी नौकरियां और पांच लाख अन्य रोजगार के अवसर देने का वादा किया था। सरकार बताए कि अब तक कितनी नियमित नियुक्तियां हुई और कितने नए रोजगार सृजित किए गए। कितने युवाओं को अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड मिला और हरियाणा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं आधुनिक कौशल शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में कितने प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए।

24 फसलों की एमएसपी खरीद और आवास योजना पर सवाल

कुमारी सैलजा ने किसानों के मुद्दे पर कहा कि भाजपा ने 24 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद का वादा किया था। सरकार प्रत्येक फसल की खरीद, लाभान्वित किसानों की संख्या और भुगतान का पूरा विवरण सार्वजनिक करे।

उन्होंने पांच लाख शहरी एवं ग्रामीण आवास उपलब्ध कराने की घोषणा पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि अब तक कितने मकान स्वीकृत हुए, कितने बनाए गए और कितने लाभार्थियों को सौंपे गए हैं।

सैलजा ने कहा कि दस आधुनिक औद्योगिक शहर विकसित करने की घोषणा पर कितना काम हुआ और इससे कितना निवेश आया, इसकी जानकारी दी जाए। बीपीएल एवं अंत्योदय परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना से कितने परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। ग्रामीण कॉलेज छात्राओं को कितने स्कूटर वितरित किए गए और जिलेवार लाभार्थियों की सूची कहां है। उन्होंने सभी मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस, प्रत्येक जिले में ओलंपिक खेल नर्सरी और हरियाणवी अग्निवीरों को सरकारी नौकरी देने की गारंटी पर भी सरकार से जवाब मांगा। उनके अनुसार, सरकार को बताना चाहिए कि कितने अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है, कितनी खेल नर्सरियां संचालित हैं और कितने पात्र पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नियुक्तियां मिली हैं। कांग्रेस महासचिव ने 36 बिरादरियों के कल्याण बोर्ड, वैज्ञानिक फार्मूले के आधार पर सामाजिक पेंशन में वृद्धि, अनुसूचित जाति एवं ओबीसी विद्यार्थियों को मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति तथा ओबीसी उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक ऋण गारंटी देने के वादों की प्रगति पर भी सवाल उठाए।

तावडू में पेठा फैक्ट्री पर संयुक्त टीम का छापा, 700 किलो तैयार पेठा मिला

अनप्लग इंडिया

तावडू। त्योहारों के सीजन में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम को लेकर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। मंगलवार को गुप्त सूचना के आधार पर नगर के रेवाड़ी पर स्थित श्री राम इंटरप्राइजेज पेठा फैक्ट्री पेठा फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान फैक्ट्री में करीब 700 किलोग्राम तैयार पेठा और लगभग 2 टन कच्चा पेठा मिला।



संयुक्त टीम में सीएम फ्लाइंग रेवाड़ी के एसआई सुरेंद्र सिंह, जिला नूंह के खाद्य सुरक्षा अधिकारी विकास जांगलान तथा प्रदूषण विभाग के एसडीओ रितेश कुमार शामिल रहे। टीम ने फैक्ट्री पहुंचकर निरीक्षण किया। मौके पर फैक्ट्री संचालक वीरेंद्र पुत्र धर्मपाल मौजूद मिला। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री संचालक की ओर से खाद्य सुरक्षा विभाग का एफएसएसएआई लाइसेंस दिखाया गया। जिस पर उसने बताया गया कि खाद्य सुरक्षा विभाग के लाइसेंस के लिए आवेदन किया हुआ है। प्रदूषण विभाग से संबंधित सीटीओ (कंसेंट टू ऑपरेट) भी प्राप्त होना पाया गया। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने तैयार पेठे से सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। अधिकारियों के अनुसार लैब रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत आगामी कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त टीम ने मौके पर ही निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की और संबंधित व्यक्ति के हस्ताक्षर भी करवाए। त्योहारों के मद्देनजर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभागीय कार्रवाई को अहम माना जा रहा है। अब प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद ही पेठे की गुणवत्ता को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।

अंबाला में शहीद स्मारक के लोकार्पण पर अमित शाह का हरियाणा की धरती पर भव्य स्वागत करेगा प्रदेश : रणबीर गंगवा

अनप्लग इंडिया

चंडीगढ़। हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का 5 नवंबर को अंबाला आगमन प्रदेश के लिए गौरव और उत्साह का बड़ा अवसर है। हरियाणा की वीरभूमि पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में हरियाणा ने विकास के साथ-साथ अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, गौरवशाली इतिहास और वीर परंपराओं को नई पहचान देने का काम किया है। अंबाला में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वीर बलिदानियों को समर्पित भव्य शहीद स्मारक का लोकार्पण इसी सोच का प्रतीक है। यह स्मारक प्रदेशवासियों के लिए गर्व का केंद्र बनेगा और आने वाली पीढ़ियों को देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले वीरों की शौर्यगाथा से जोड़ने का काम करेगा। गंगवा ने कहा कि हरियाणा की मिट्टी ने हमेशा देश की रक्षा और सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर सपूतों को जन्म दिया है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भी इस धरती के वीरों ने अदम्य साहस और बलिदान की मिसाल पेश की थी। अंबाला में बनकर तैयार हुआ यह स्मारक उन ज्ञात-अज्ञात बलिदानियों को सच्ची श्रद्धांजलि है, जिनके संघर्ष और त्याग की बदौलत देश की आजादी की नींव मजबूत हुई। यहां 700 से अधिक वीर बलिदानियों के नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किए गए हैं। आधुनिक तकनीक और आकर्षक प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम की गौरव गाथा को इस तरह सहेजा गया है कि हर आगंतुक उस दौर के संघर्ष और बलिदान को महसूस कर सके। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा हरियाणा के लिए एक यादगार अवसर होगा। शहीद स्मारक का लोकार्पण प्रदेश



के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ेगा। यह केवल ईंट-पत्थर से बना स्मारक नहीं, बल्कि देश भक्ति, त्याग, साहस और राष्ट्रीय स्वाभिमान की जीवंत प्रेरणा है। अमित शाह अंबाला के गांधी ग्राउंड में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गंगवा ने प्रदेशवासियों से इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बनने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गर्मजोशी से स्वागत करने का आह्वान किया।

'लोकतंत्र बचाने' की बात करने से पहले वोट चोरी और चुनावी पारदर्शिता पर जवाब दें अमित शाह : राव नरेंद्र सिंह

अनप्लग इंडिया

करनाल। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरियाणा दौरे से पहले भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अमित शाह को 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' मार्च और जनसभा के जरिए लोकतंत्र की बात करने से पहले प्रदेश की जनता के उन सवालों का जवाब देना चाहिए, जो कथित वोट चोरी, चुनावी पारदर्शिता, संवैधानिक जवाबदेही और कानून-व्यवस्था से जुड़े हैं। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि अमित शाह कल हरियाणा आ रहे हैं। वे करनाल में भाजपा की ओर से आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' मार्च का नेतृत्व करेंगे और अंबाला में जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन लोकतंत्र बचाने की बात करने वाली भाजपा को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े गंभीर सवालों पर अब तक संतोषजनक जवाब क्यों नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल नारों, जुलूसों और राजनीतिक आयोजनों से सुरक्षित नहीं होता, बल्कि इसकी रक्षा पारदर्शिता, जवाबदेही, संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और जनता के जनादेश के सम्मान से होती है।

राहुल गांधी के वोट चोरी संबंधी आरोपों पर मांगा जवाब-राव नरेंद्र

संक्षिप्त डायरी

पहले अफसरों पर प्राथमिकी, अब चार्जशीट में क्लीन चिट, ठेकेदार-सुरक्षाकर्मी को बनाया दोषी

अनप्लग इंडिया

कानपुर । कल्याणपुर स्थित राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में जून 2026 के दौरान 722 हरे पेड़ काटे जाने के चर्चित मामले में पुलिस ने कोर्ट में 19 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी है। खास बात यह है कि विवेचना के बाद पुलिस ने संस्थान की डायरेक्टर सीमा परोहा समेत अन्य अधिकारियों के नाम चार्जशीट से हटाकर उन्हें क्लीन चिट दे दी है, जबकि शुरूआती प्राथमिकी में इन्हीं अफसरों के नाम दर्ज थे। कानपुर में कल्याणपुर स्थित राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआई) में 722 हरे पेड़ काटने के मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। चार्जशीट से एनएसआई की डायरेक्टर सीमा परोहा व अन्य अधिकारियों के नाम हटा दिए हैं, जबकि पूरा ठीकरा टिंबर संचालक, ठेकेदार व एनएसआई के सुरक्षा गार्ड पर डाल दिया है। मामले में पहले इन्हीं अफसरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अब पुलिस ने कुल चार लोगों के खिलाफ 19 पेज की चार्जशीट कोर्ट में पेश की है। इसमें नौ गवाह बनाए गए हैं। विवेचना में 22 पर्चे काटे गए हैं। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में जून 2026 में गुपचुप तरीके से 722 हरे पेड़ काटे जाने का मामला में तत्कालीन क्षेत्रीय वन अधिकारी राकेश कुमार पांडेय ने एनएसआई की निदेशक सीमा परोहा, संपदा अधिकारी विनय कुमार, फार्म प्रबंधक अशोक कुमार, निजी सुरक्षा कमांडर उदय प्रताप सिंह, अनवरगंज के तिवारी वुड मर्चेंट के मालिक व कुछ अज्ञात पर कल्याणपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके साथ ही वन विभाग ने अपनी जांच रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी थी। मामले में पुलिस ने सीमा, अशोक और विनय के नाम हटाते हुए उन्हें क्लीनचिट दे दी, जबकि पेड़ों को काटने का दोषी मेसर्स वुड मर्चेंट की प्रोपराइटर आरती तिवारी, ठेका लेने वाले ठेकेदार बिठूर के बैकुंठपुर निवासी राजेंद्र कुमार गौतम, अजय कुमार गौतम और एनएसआई के सुरक्षा कमांडर उदय प्रताप सिंह राठौर को बनाया है। वन विभाग की रिपोर्ट में पाए जा चुके हैं दोषी वन विभाग ने थाने में एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही स्वयं भी जांच शुरू की थी। एसडीओ आशीष जैन ने अपनी जांच में एनएसआई की डायरेक्टर व अन्य अधिकारियों को दोषी पाया था। अपनी रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी थी। मामले में केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए निदेशक सीमा परोहा और संपदा अधिकारी विनय कुमार को निलंबित कर दिया था। ऐसे में पुलिस की जांच में दोनों का बेदाग निकलना गले नहीं उतर रहा। कर्मचारी संघ ने की शिकायत, वन विभाग टीम घुस न सकी थी एनएसआई कर्मचारी संघ के मंत्री अजीत कुमार, सभापति अरविंद कुमार सविता ने परिसर में लगे प्रोसोपिस, नीम, कनेर, शीशम, यूकेलिपटिस, जंगल जलेबी, चिलबिल, छितवन, लसोढ़ा आदि हरे पेड़ कटे देख वन विभाग को सूचना दी थी। क्षेत्रीय वन अधिकारी 27 मई 2026 को टीम के साथ जांच करने पहुंचे, तो उन्हें गेट के अंदर नहीं घुसने दिया गया। परिसर की कॉम्बिंग कर जबरन ताला खुलवाया 29 मई को टीम दोबारा जांच को पहुंची, तो गेट पर मौजूद सुरक्षा कर्मी ने निदेशक सीमा परोहा की अनुमति न मिलने का हवाला देकर लौटा दिया। इसपर 30 मई को कानपुर और बिधनू रेंज की एक संयुक्त टीम एनएसआई पहुंची और पूरे परिसर की कॉम्बिंग कर जबरन ताला खुलवाया गया। अंदर पहुंचने पर पेड़ कटे मिले। मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद विवेचना दरोगा शुभम पांडेय ने विवेचना की है। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर निदेशक, संपदा अधिकारी, फार्म प्रबंधक के नाम हटाए गए हैं। जांच के क्रम में दो नाम सामने भी आए। जिसके आधार पर चार के खिलाफ चार्जशीट कुछ दिन पहले न्यायालय में पेश की गई है।

दिवाली पर सात दिन चार जगहों पर मुफ्त पार्किंग की सौगात, बाजारों से हटेगा अतिक्रमण

एजेंसी

कानपुर । दीपोत्सव के दौरान बाजारों में उमड़ने वाली भारी भीड़ और जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई यातायात समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया है कि पांच नवंबर से लगातार सात दिनों तक शहर के चार प्रमुख स्थानों में वाहन पूरी तरह निशुल्क पार्क किए जा सकेंगे। कानपुर में दिवाली पर बाजारों में खरीदारी के लिए निकलने वालों के लिए राहत की खबर है। प्रशासन ने जाम से बचाने और पार्किंग की सुविधा बढ़ाने के लिए विशेष योजना तैयार की है। इसके तहत फूलबाग, परेड और पनचक्की स्थित मल्टीलेवल पार्किंग में पांच नवंबर से लगातार सात दिन तक वाहन पार्किंग निशुल्क रहेंगी। परेड स्थित रामलीला मैदान में भी वाहन खड़े करने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही झकरकटी बस अड्डे पर दबाव कम करने के लिए पश्चिमी जिलों से लखनऊ और दूसरे शहरों को जाने वाली बसों को शहर में प्रवेश देने के बजाय बाईपास से निकाला जाएगा। वहीं पांच नवंबर से सिग्नेचर सिटी बस अड्डे की बसें सरैया क्रॉसिंग होकर चलेंगी। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई यातायात समीक्षा बैठक में ये फैसले लिए गए। झकरकटी बस अड्डे नहीं आएंगी बसें फैसले के अनुसार आगरा, इटावा और गाजियाबाद की ओर से आने वाली जिन बसों का गंतव्य कानपुर नहीं, बल्कि लखनऊ या अन्य शहर हैं। वे झकरकटी बस अड्डे नहीं आएंगी। इन्हें भौंती से नौबस्ता फ्लाईओवर होते हुए रामादेवी मार्ग से आगे भेजा जाएगा। वहीं, विकासनगर स्थित सिग्नेचर सिटी बस अड्डे से लखनऊ, हरदोई और रायबरेली मार्ग की बसों का संचालन बढ़ेगा। व्यवस्था में लापरवाही न बरतने के निर्देश पांच नवंबर से सरैया क्रॉसिंग शुरू होने के बाद इन बसों को इसी रास्ते से चलाया जाएगा।

डॉ. अनिल जोशी बोले- अल नीनो से बढ़ेंगी फ्लैश फ्लड और पॉकेट रेन की घटनाएं, दी ये बड़ी चेतावनी

एजेंसी

कानपुर । कानपुर पहुंची 3,000 किलोमीटर लंबी प्रकृति पथ साइकिल यात्रा के दौरान हेस्को के संस्थापक व पद्मश्री पर्यावरणविद डॉ. अनिल प्रकाश जोशी ने जलवायु परिवर्तन और अल-नीनो के गंभीर खतरों पर चिंता जताई। अल नीनो और पश्चिमी विक्षोभ जैसी मौसमी प्रणालियों में बदलाव जलवायु परिवर्तन के खतरे का संकेत है। इनके कारण फ्लैश फ्लड और पॉकेट रेन की घटनाएं बढ़ेंगी। इसका सबसे बुरा असर स्थानीय छोटी नदियों पर पड़ेगा। बारिश का चक्र प्रभावित होने से ये नदियां या तो धीरे-धीरे सूख जाएंगी या फिर अचानक आई बाढ़ से आसपास के इलाकों में तबाही मचाएंगी। हिमालय से निकलने वाली नदियों पर भी संकट गहराएगा। यह कहना है हिमालयन इन्वायरनमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन आगेर्नाइजेशन (हेस्को) के प्रमुख पर्यावरणविद पद्मश्री डॉ. अनिल प्रकाश जोशी का। डॉ. जोशी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए निकाली गई तीन हजार किलोमीटर लंबी प्रकृति पथ साइकिल यात्रा लेकर शहर पहुंचे थे। यात्रा सात राज्यों से गुजरेगी। उन्होंने बताया कि यात्रा नेपाल के जनकपुरधाम से शुरू होकर उत्तराखंड के देहरादून तक जाएगी। डॉ. जोशी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण पूरा मौसमी सिस्टम असंतुलित हो रहा है। दुनिया के दो-तिहाई समुद्रों का तापमान बढ़ रहा है। इससे बादल टुकड़ों में बन रहे हैं और सीमित क्षेत्रों में अचानक तेज बारिश हो रही है। वहीं, बर्फबारी कम होने से हिमखंड टूट रहे हैं। हिमालय में बर्फ की मात्रा घटने का असर वहां से निकलने वाली नदियों पर पड़ेगा। ये नदियां धीरे-धीरे सूखने लगेंगी। उन्होंने कहा कि छोटी नदियों में पानी का मुख्य स्रोत बारिश है। मानव समाज को संकट में डाल सकती है जल की कमी बारिश सामान्य रूप से नहीं होने पर ये नदियां सूख जाएंगी। वहीं एक ही स्थान पर अत्यधिक बारिश होने से अचानक बाढ़ आ सकती है। डॉ. जोशी ने कहा कि इस संकट से बचने का रास्ता प्रकृति से जुड़ना और पेड़-पौधों का संरक्षण करना है। हाईवे पर तापमान गांवों की तुलना में अधिक महसूस होता है। यह अंतर बताता है कि प्रकृति का संरक्षण कितना जरूरी है। उन्होंने कहा कि विश्व का पर्यावरण एक-दूसरे से जुड़ा है और नदियां जीवन रेखा हैं। इनमें जल की कमी पूरे मानव समाज को संकट में डाल सकती है।

अखबार में लिपटी शराब, शरीर पर टेप से चिपकाकर तस्करी... ऐसा जुगाड़ देख पुलिस भी रह गई हैरान

अनप्लग इंडिया

चंदौली। चंदौली जिले में पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में 18 महिलाओं समेत 33 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्कर पर्स और कपड़ों में छिपाकर शराब बिहार ले जाते थे। तस्करी का ऐसा जुगाड़ देख कर पुलिस भी हैरान रह गई। बिहार में शराबबंदी के बावजूद वहां शराब की बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है। वहीं, शराब तस्करी के लिए आरोपियों ने भी अनोखा तरीका निकाला था। पुलिस से बचने के लिए शराब की बोतलों को अखबार में लपेटकर पारदर्शी टेप से चिपकाया जाता था। पुरुष इन्हें पिट्ठू बैग और कपड़ों के थैलों में रखते थे, जबकि महिलाएं पर्स, सूटकेस और कपड़ों के साथ शरीर पर टेप से चिपकाकर शराब की बोतलें बिहार ले जाती थीं। चंदौली कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को अंतरराज्यीय शराब



तस्करों के गिरोह का पदार्फाश करते हुए 18 महिलाओं समेत 33 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कस्बे के वार्ड नंबर पांच स्थित बंद पड़े चंदौली रेस्टोरेंट में छापा मारकर 520.7 लीटर अवैध शराब बरामद की। इसमें विभिन्न ब्रांड की 2234 बोतलें, टेट्रा पैक और पाउच शामिल हैं। इसके अलावा शराब बिक्री के 37,690 रुपये नकद, एक टेंपो, दो मोटरसाइकिल और एक मोपेड भी बरामद की गई। मंगलवार को प्रभारी निरीक्षक त्रिवेणी सिंह पुलिस टीम के साथ सकलडीहा तिराहे पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार दो लोगों को रोकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखकर बाइक चालक वाहन मोड़कर भाग निकला, जबकि पीछे बैठा व्यक्ति फिसलकर गिर गया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसकी पहचान बिहार के वैशाली जिले के सुमंत कुमार के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके पिट्ठू बैग से शराब बरामद हुई। पूछताछ में उसने वार्ड नंबर पांच स्थित बंद पड़े चंदौली रेस्टोरेंट में शराब की बड़ी खेप जमा होने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस टीम ने रेस्टोरेंट पर दबिश दी। सीढ़ियों के नीचे बने दरवाजे से अंदर पहुंची पुलिस को कम रोशनी में बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं शराब की बोतलों की पैकिंग करते मिले। पुलिस ने घेराबंदी कर सभी 33 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ट्रेनों, बसों और निजी वाहनों से बिहार भेजते थे शराब पुलिस की जांच में सामने आया कि रेस्टोरेंट में शराब इकट्ठा कर छोटी-छोटी खेप में ट्रेनों, बसों और निजी वाहनों से बिहार भेजी जाती थी। पुलिस ने मामले में आबकारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। रेस्टोरेंट के मालिक और शराब ठेके से जुड़े संतोष गुप्ता की भूमिका भी पूछताछ में सामने आई है। रेस्टोरेंट के भीतर सीढ़ियों के नीचे बने दरवाजे से आने-जाने की व्यवस्था थी। यहां शराब की बोतलों को अखबारों में लपेटकर अलग-अलग खेप तैयार की जाती थी। पुलिस ने रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को रिपोर्ट भेजी है। गिरफ्तार आरोपियों में तीन चंदौली के शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार आरोपियों में तीन चंदौली जिले के हैं। इनमें रोहित कुमार निवासी बसिला, धर्मेंद्र खरवार निवासी फगुईया और सन्नी गुप्ता निवासी दिघवट, चंदौली शामिल हैं। बाकी सभी आरोपी बिहार के विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं। इनमें चंद्रप्रकाश निवासी दुभारा, पटना, शंकर चौहान निवासी सब्बलपुर, नालंदा, श्रीनिवास पासवान निवासी बनरसिया, सासाराम, अखिलेश कुमार निवासी बहरामपुर, वैशाली, लालबाबू महतो निवासी सब्बलपुर, पटना, सुरेंद्र कुमार यादव निवासी बहरामपुर, वैशाली और राधेकिशुन राय निवासी जफराबाद, वैशाली शामिल हैं। इसी तरह मंजय कुमार निवासी बहरामपुर, वैशाली, मुकेश महतो निवासी सब्बलपुर, पटना, राजकुमार राय निवासी संस्तापुर, वैशाली और सुमंत कुमार निवासी तयोपुर, वैशाली को गिरफ्तार किया गया है।

बिहार की 18 महिलाएं भी गिरफ्तार शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार महिलाओं में शैला देवी निवासी पटना सिटी, सविता देवी निवासी सिगौड़ी, पटना, सुनीता देवी निवासी मरसलामी, पटना, रेनू देवी निवासी चंडी, नालंदा, बेबी देवी निवासी कुसरुपुर, पटना, ज्योति देवी निवासी महनार, वैशाली, रिंकू देवी निवासी फतुहा, पटना और सरिता देवी निवासी बाईपास, पटना शामिल हैं।

धनतेरस से पहले बाजार में खरीदारी का अलग-अलग रंग

अनप्लग इंडिया

झांसी। धनतेरस का त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में खरीदारी को लेकर हलचल शुरू हो गई है। इस वर्ष बाजार में खरीदारी का रुख अलग-अलग देखने को मिल रहा है। कहीं ग्राहक महंगे सामान और गिफ्टिंग आइटम खरीदने से बच रहे हैं, तो कहीं रोजमर्रा की जरूरतों के सामान की मांग लगातार बनी हुई है। सीपरी बाजार स्थित नगरिया रसोई कल्चर के संचालक अमन अग्रवाल ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार बिक्री थोड़ी धीमी है। बाजार की स्थिति सामान्य बनी हुई है। ग्राहक फिलहाल जरूरत के सामान को प्राथमिकता दे रहे हैं और महंगी चीजें खरीदने से बच रहे हैं। गिफ्टिंग आइटम्स की खरीदारी में भी कमी आई है। जहां पहले ग्राहक एक हजार रुपये तक के गिफ्ट खरीदते थे, वहीं अब चार सौ से पांच सौ रुपये की रेंज में सामान पसंद कर रहे हैं। अमन ने बताया कि लोगों की ईएमआई, अन्य खर्चे और निवेश जैसी जिम्मेदारियां भी खरीदारी के बजट को प्रभावित कर सकती हैं। ध्यानचंद स्टेडियम के सामने स्थित सेलिब्रेशन सुपर मार्केट के संचालक हरीश पटपटिया ने बताया कि उनके यहां बाजार की स्थिति अच्छी है। भले ही दूसरी चीजों की खरीदारी में कुछ कमी देखने को मिल रही हो, लेकिन रोजमर्रा के जरूरत के सामान की मांग में कोई खास गिरावट नहीं आई है। उनके सुपरमार्केट में प्रतिदिन करीब आठ सौ से एक हजार ग्राहक खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। बदलते दौर में घरों को आधुनिक और आकर्षक लुक देने के लिए इंटीरियर डिजाइनिंग और मॉड्यूलर किचन की मांग लगातार बढ़ रही है। झोकन बाग स्थित लिविंग स्पेस स्टूडियो में आधुनिक डिजाइन और बेहतरीन ब्रांड्स के उत्पादों को उपलब्ध करा रहा है। स्टूडियो के संचालक दीपांशु यादव ने बताया स्लीक और क्राइसिल जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड्स के आधुनिक किचन, स्टाइलिश इंटीरियर और घर की खूबसूरती बढ़ाने वाले उत्पाद मौजूद हैं। इसके साथ ही ग्राहकों की जरूरत और पसंद के अनुसार टूडी एवं श्रीडी इंटीरियर डिजाइनिंग और डिजाइन प्लान भी तैयार किए जा रहे हैं, जिससे ग्राहक काम शुरू होने से पहले ही अपने घर और किचन का प्रस्तावित लुक देख सकते हैं।

एक घंटे देरी से जागेंगे ठाकुरजी, ठंड से बचाव को लगेगा मेवे-केसर का भोग

अनप्लग इंडिया

मथुरा सर्दियों में बांकेबिहारी के दर्शन के समय में बदलाव किया जाएगा। इसके तहत सुबह दर्शन एक घंटे देर से शुरू होंगे, जबकि रात्रि में मंदिर के पट एक घंटे पहले बंद कर दिए जाएंगे। साथ ही ठाकुरजी को ठंड से बचाव के लिए भोग सेवा में भी बदलाव होगा। दिवाली के बाद मौसम में आती ठंडक में अब आराध्य ठाकुर बांकेबिहारी के दर्शन के समय के साथ सेवा बदलाव हो जाएगा। जिस तरह सर्दियों में घरों में बच्चों को रजाई से देर तक बाहर नहीं निकाला जाता, उसी वात्सल्य भाव के तहत अब ठाकुरजी को एक घंटा अधिक विश्राम कराया जाएगा। दिवाली के बाद भाईदूज 11 नवंबर से ठाकुरजी की दिनचर्या में शीतकालीन सेवा व्यवस्था में बदलाव हो जाएगा। दर्शन का नया समयबांकेबिहारी मंदिर में गर्मी में



सुबह 7:45 से दोपहर 12:30 बजे तक भक्तों को ठाकुरजी के दर्शन होते थे। अब सर्दियों में भाईदूज से सुबह 8:45 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक श्रद्धालु बांकेबिहारी के दर्शन कर सकेंगे। शाम के दर्शन के समय में भी बदलाव किया गया है। गर्मी में शाम 5:30 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक भक्तों को आराध्य के दर्शन होते थे, अब सर्दियों में भाईदूज से शाम 4:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक दर्शन होंगे। मंदिर के सेवियत हिमांशु गोस्वामी ने बताया कि मौसम परिवर्तन के साथ ठाकुरजी की सेवा में बदलाव की यह परंपरा रही है। इसके तहत सुबह दर्शन एक घंटे देर से शुरू होंगे, जबकि रात्रि में मंदिर के पट एक घंटे पहले बंद कर दिए जाएंगे। इस प्रकार सुबह और शाम दोनों समय में एक-एक घंटे का बदलाव किया गया है। भोग में केसर, मेवा और गर्म पकवानों की बढ़ेगी मिठास सर्दियों के आगमन के साथ ही ठाकुरजी के खानपान में भी गर्माहट बढ़ाई जाएगी। सुबह के बालभोग में केसरयुक्त हलवा और विशेष लड्डू अर्पित किए जाएंगे। जभोग में दूध-दही से बने तरल पदार्थों की मात्रा कुछ कम करके, सूखे मेवे और गर्म तासीर वाले पकवानों की मात्रा बढ़ाई जाएगी। शीतकालीन पोशाक और लाड़-दुलार की परंपरा ठंड से बचाव के लिए ठाकुरजी अब हल्की पोशाक के स्थान पर मोटे और गर्म कपड़ों से तैयार विशेष वस्त्र धारण करेंगे। सेवायत गोस्वामी का कहना है कि यह बदलाव केवल समय परिवर्तन भर नहीं है, बल्कि यह अपने आराध्य के प्रति उस वात्सल्य और लाड़-दुलार की अनूठी परंपरा का हिस्सा है, जिसमें ठाकुरजी को घर के छोटे बालक की तरह लाड़-प्यार के साथ सेवा की जाती है।

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में पराठा, दाल, चावल, चिकन और सब्जी का चख सकेंगे स्वाद

एजेंसी

वाराणसी। स्लीपर वंदे भारत ट्रेन में भोजन का मैन्यू आईआरसीटीसी की ओर से जारी किया गया है। यह ट्रेन रात 8.50 बजे से वाराणसी जंक्शन से शुक्रवार को छोड़ हर दिन वाराणसी से चलेगी जबकि शनिवार को छोड़ हर दिन लोग दिल्ली से वाराणसी तक का सफर कर सकेंगे। रात में यात्रियों को 120 ग्राम चावल, तीन रोटी या 2 पराठा, दाल, पनीर सहित अन्य सब्जियों के साथ ही चिकन भी मिलेगा। मिठाई और दही का भी स्वाद यात्री चख सकेंगे। खाने के दौरान यात्रियों को नमक, मिर्च, अचार का पैकेट भी मिलेगा। सुबह के समय



चाय/कॉफी/ग्रीन टी और दो बिस्किट भी मिलेगा। हालांकि चाय को लेकर आईआरसीटीसी की ओर से यह भी तय किया गया है कि अगर ट्रेन लेट होती है तो यात्रियों को सुबह की चाय मिलेगी। ऐसा इसलिए कि इस ट्रेन के वाराणसी पहुंचने का समय सुबह 6.10 बजे से है। इस बीच दूसरे दिन भी स्लीपर ट्रेन से दिल्ली तक यात्रा करने वालों की संख्या अधिक रही।

चंदौली की 29 दीपावली बीतीं, फिर भी चार प्रमुख प्रवेश मार्गों से नहीं मिटा अंधेरा

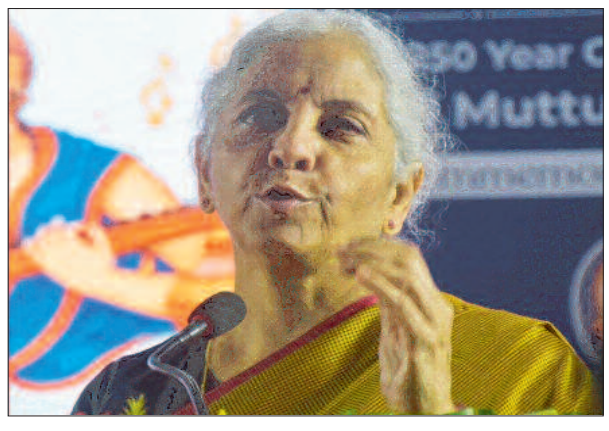
एजेंसी

पीडीडीयू नगर। वाराणसी से अलग होकर चंदौली को जिला बने 29 साल हो गए, लेकिन प्रमुख प्रवेश मार्गों की तस्वीर आज तक नहीं बदली। जिले में प्रवेश करते ही बेहतर सड़क और रोशनी की उम्मीद करने वाले राहगीरों को रात होते ही अंधेरे से जूझना पड़ता है। अंधेरे और तेज रफ्तार की वजह से हादसे होते हैं। इससे कई लोगों की जान भी जा चुकी है। पड़ाव-पीडीडीयू नगर, ककरैत-तलासपुर, इलिया-बिहार और जमानिया-चंदौली मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था की बदहाली विकास के दावों की पोल खोल रही है। कहीं करोड़ों की लागत से बनी चौड़ी सड़क पर खंभे और लाइटें लगने के एक साल बाद भी रोशनी नहीं हुई तो कहीं वर्ष 2015 में लगाई गई हाईमास्ट लाइट एक साल से अधिक समय से खराब है। इलिया में यूपी-बिहार को जोड़ने वाला मार्ग पांच साल से जर्जर है और यहां प्रकाश व्यवस्था भी नदारद है। संवाद रोज गुजरते हैं 1200 ट्रक समेत 10 हजार से ज्यादा वाहन जिले के सबसे प्रमुख पड़ाव-पीडीडीयू नगर मार्ग पर सिक्सलेन निर्माण के बावजूद रात का अंधेरा दूर नहीं हुआ। करीब आठ किलोमीटर लंबे मार्ग पर एक साल पहले बिजली के खंभे और लाइटें लगा दी गईं थीं, लेकिन अब तक उन्हें चालू नहीं किया जा सका है। वाराणसी से चंदौली आने का यह प्रमुख रास्ता है। इस पर 24 घंटे वाहनों की आवाजाही रहती है। आंकड़ों के अनुसार, इस मार्ग से प्रतिदिन करीब 1200 ट्रक, चार हजार दोपहिया और पांच हजार चार पहिया वाहन गुजरते हैं। यानी रोजाना 10 हजार से ज्यादा वाहनों का दबाव रहता है। पिछले 20 दिनों में यहां 10 से ज्यादा छुट्टा पशुओं की मौत हो चुकी है। वहीं, करीब तीन महीने पहले अंधेरे के कारण एक युवक की भी जान जा चुकी है। ककरैत और तलासपुर प्रवेश द्वार पर भी नहीं रोशनी यूपी-बिहार और गाजीपुर-चंदौली को जोड़ने वाले ककरैत और तलासपुर प्रवेश मार्गों पर भी प्रकाश की व्यवस्था बदहाल है। ककरैत में वर्ष 2015 में लगाई गई हाईमास्ट लाइट एक साल से खराब है। दुर्गावती-ककरैत का नौ किलोमीटर और जमानिया-ककरैत का आठ किलोमीटर लंबा मार्ग दोनों राज्यों और जिलों के बीच आवागमन का प्रमुख रास्ता है। इन मार्गों से रोज 500 से ज्यादा वाहन गुजरते हैं। रात में रोशनी नहीं होने से वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं, जमानिया-चंदौली मार्ग पर भी पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं होने से रात का सफर जोखिम भरा बना हुआ है।

निर्मला सीतारमण ने कहा- मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचनाओं में शैव

एजेंसी

वाराणसी। आईआईटी बीएचयू के कार्यक्रम में केंद्रीय वित्तमंत्री ने 23 मिनट तक स्कूली बच्चों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुत्तुस्वामी दीक्षितर के सम्मान में 250 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। साथ ही पुस्तक का लोकार्पण भी किया। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने महान वीणावादक मुत्तुस्वामी दीक्षितर के सम्मान में 250 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। साथ ही अमर गुरुगुहम् पोट्टवाम्-पुस्तक का लोकार्पण किया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचनाओं की खासियत यह थी कि उनमें शैव परंपरा, शाक्त उपासना और तांत्रिक साधना के कई तत्व समाहित थे। करीब 23 मिनट के संबोधन में

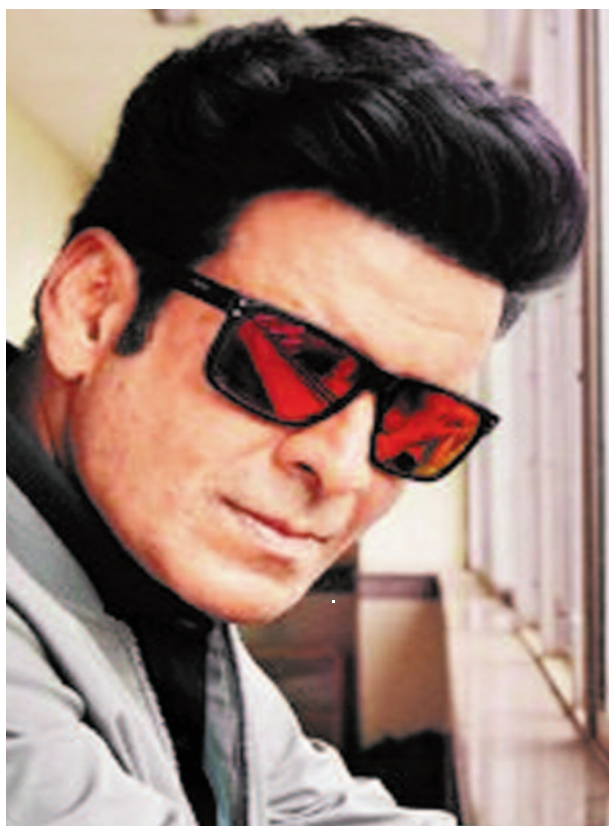


उन्होंने स्कूली बच्चों को सांस्कृतिक आयोजनों से जोड़ने पर जोर दिया। कहा कि हम ज्यादातर समय फोन में व्यस्त रहते हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने से भारतीय संस्कृति, भाषा और साहित्य को जानने-समझने का अवसर मिलता है। भारत के बारे में जानने के लिए बच्चों का ऐसे आयोजनों में आना जरूरी है। आईआईटी बीएचयू की ओर से बुधवार को स्वतंत्रता भवन में आयोजित मुत्तुस्वामी दीक्षितर सम्मान समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब मुत्तुस्वामी काशी में थे, तब उनकी वीणा का स्वरूप आज की वीणा से अलग था। वीणा के बाईं ओर के हिस्से पर जानवर का एक छोटा-सा मुख बना होता है, जो नीचे की ओर झुका रहता है। जबकि मुत्तुस्वामी को काशी से जो वीणा मिरी, उसमें यह मुख ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है। यह वीणा आज भी उनके परिवार के पास है और परिजन इसकी पूजा करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचनाओं की तुलना प्रसिद्ध यात्रा-पुस्तक शृंखला लोनली प्लेनेट से की। उन्होंने कहा कि आज किसी स्थान के बारे में जानना हो तो लोग गूगल की मदद लेते हैं, जबकि पहले यात्री लोनली प्लेनेटजैसी पुस्तकों के सहारे अनजान जगहों तक पहुंचते थे। काशी में देवी की स्तुति करते हुए उन्होंने काशी विश्वलक्ष्मी का वर्णन किया है।

तालपुरा मंडी में 1.52 करोड़ से विकसित होंगी भंडारण सुविधाएं

एजेंसी

झांसी। तालपुरा मंडी में किसानों, व्यापारियों और पल्लेदारों के लिए नीलामी, अस्थायी भंडारण, प्रकाश और पेयजल सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। मंडी परिसर में मौजूदा संरचनाओं का बेहतर उपयोग करते हुए अस्थायी भंडारण और दुकानों की व्यवस्था विकसित होगी। उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद ने इन कार्यों के लिए 1.52 करोड़ की स्वीकृति दे दी है। स्वीकृत बजट में 1.42 करोड़ से निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं। जबकि, 10.13 लाख रुपये से विद्युत एवं संबंधित सुविधाओं का सुधार होगा। परियोजना में कृषि उपज की नीलामी से लेकर मंडी में कार्यरत श्रमिकों की आवश्यकताओं तक विभिन्न व्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। मंडी परिसर में उपलब्ध संरचनाओं में पार्टिशन लगाकर अस्थायी भंडारण और दुकानों के लिए स्थान तैयार किया जाएगा। इससे मौजूदा भवनों का अधिक प्रभावी उपयोग हो सकेगा और कृषि उपज की आवक के दौरान भंडारण, व्यापारिक गतिविधियों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था उपलब्ध होगी। पल्लेदारों के लिए बने शेड का भी सुधार कराया जाएगा। मंडी में कृषि उपज की लोडिंग-अनलोडिंग और अन्य कार्यों में लगे पल्लेदारों को इससे बेहतर कार्यस्थल उपलब्ध हो सकेगा। मंडी परिषद के निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मंडियों का विकास केवल नई संरचनाओं के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग और किसानों एवं व्यापारियों की व्यावहारिक आवश्यकताओं को पूरा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।



फिल्म इंडस्ट्री कोई परिवार नहीं, ये भ्रम है

मनोज बाजपेयी इन दिनों बॉलीवुड से कुछ ज्यादा ही नाराज चल रहे हैं। चार बार नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीत चुके मनोज की पिछली दो फिल्में 'लास्ट मैन इन टावर' और 'गर्वनर' बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई हैं। इन दिनों वह नेटफ्लिक्स पर रिलीज अपनी फिल्म 'गजब रात' को लेकर चर्चा में हैं। हालांकि, इस फिल्म को भी बहुत अच्छे रिव्यूज नहीं मिले हैं। इस बीच 57 साल के एक्टर ने फिल्म इंडस्ट्री को 'एक बड़ा परिवार' मानने वाली आम धारणा को चुनौती दी है। 'गजब रात' के प्रमोशन के दौरान मनोज बाजपेयी ने कहा कि 'यह इंडस्ट्री बकवास है' और यहां किसी को किसी की कोई कद्र नहीं है।

बातचीत में मनोज बाजपेयी ने कहा, 'अगर आप मुझे एक उदाहरण मानना चाहें, तो मैं एक उदाहरण हूं। मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूं, फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैं इसका हिस्सा हूं। जरूरी नहीं कि आप बांद्रा से ही हों। आप मलाड में रहकर भी एक्टिंग कर सकते हैं। अहम बात यह है कि आप जो भी करें, वह अच्छा हो। बाकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में कोई 'परिवार' या 'बिरादरी' जैसी चीज नहीं होती। सबसे बड़ा भ्रम यही है कि यह इंडस्ट्री एक परिवार है। यह किसी परिवार की तरह नहीं है। सबके ऑफिस अलग-अलग हैं, कोई किसी के साथ पार्टी नहीं करता और अगर किसी को किसी की फिल्म पसंद आ जाए, तो भी कोई फोन करके तारीफ नहीं करता।'

मनोज बाजपेयी ने दो टूक कहा कि इंडस्ट्री में कोई भी एक्टर किसी दूसरे की सफलता देखकर खुश नहीं होता। कोई भी डायरेक्टर खुद को दूसरे निर्देशक से कम नहीं समझता। कोई भी प्रोडक्शन हाउस किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस को ज्यादा पैसे कमाते देखकर खुश नहीं होता। इसलिए, इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए।

साल 2024 में ओटीटी पर रिलीज 'गुलमोहर' के लिए नेशनल अवॉर्ड पाने वाले मनोज बाजपेयी कहते हैं, 'आप अकेले आए हैं और जब आप जाएंगे, तब भी अकेले ही जाएंगे। वैसे, इस तरह की सलाह देने के लिए मैं शायद सही इंसान नहीं हूं। मैं आपको पहले ही यह डिस्क्लेमर दे देता हूं, क्योंकि मैं किसी को भी इस तरह से नहीं मानता। मैं अपना काम करता हूं, अपने पैसे लेता हूं और घर वापस आ जाता हूं।'

राज एंड डीके की सीरीज 'द फैमिली मैन' फेम एक्टर ने आगे काम के प्रति अनुशासन के महत्व पर जोर दिया। कहा कि अनुशासन लोगों को उनके करियर में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहने में मदद करता है। लेकिन साथ ही कहते हैं, 'ऐसे कई अभिनेता हैं जो अनुशासित नहीं हैं, फिर भी उनकी तारीफ होती है और वे अच्छा पैसा भी कमाते हैं। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे अनुशासित रहना पसंद है।



अब सेट पर बात नहीं करते एक्टर्स, सब वैनिटी वैन और फोन में बिजी

जब मनोज बाजपेयी से पूछा गया कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा क्या नापसंद है, तो उन्होंने सेट पर होने वाले असमान व्यवहार का जिक्र किया। पुराने दौर को याद करते हुए कहा कि उस जमाने में एक्टर्स शूटिंग के बीच एक-दूसरे के साथ समय बिताते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया और वैनिटी वैन में रहते हैं। वह कहते हैं, 'मैं बहुत परेशान रहने वाला इंसान हूं। कई चीजों को लेकर मेरे मन में काफी उलझनें और बेचैनी रहती है। पहली बात, हर सेट पर बराबरी होनी चाहिए। सबको एक जैसा खाना मिलना चाहिए। दूसरी बात, कलाकारों को एक-दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। पहले के समय में, कलाकार साथ बैठकर बातें करते थे। अगर उनका शेड्यूल इजाजत देता, तो वे शाम को भी मिलते थे, खूब गपशप करते थे और मजे करते थे। लेकिन अब, हर कलाकार अपनी वैन में चला जाता है और बस सोशल मीडिया पर लगा रहता है।'

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

सेंसेक्स 383, निफ्टी 149 अंक गिरा

मुम्बई ।

घरेलू शेयर बाजार बुधवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में तेजी के साथ बंद हुए। बाजार में ये उछाल दुनिया भर के बाजारों से मिले अच्छे संकतों के साथ ही खरीददारी हावी रहने से आया है। आज कारोबार के दौरान बीईएल, टाइटन, इंडिगो, बजाज फाइनेंस, आईटीसी, अडाणी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व के शेयरों में तेजी रही। वहीं दूसरी ओर, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस के शेयर गिरे। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 383.55 अंकों की बढ़त के साथ ही 77,301.40 अंकों पर बंद हुआ। जबकि 50 शेयरो वाला , एनएसई निफ्टी 149.75 अंकों से उछलकर 23,960.60 अंकों पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स की 30 में से 19 कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ ही ऊपर आये जबकि शेष 9 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ ही नीचे आये। वहीं दूसरी ओर, निफ्टी 50 की 50 में से 36 कंपनियों के शेयर बढ़त पर बंद हुए और बाकी की 14 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ नीचे आये। सेंसेक्स की कंपनियों में शामिल सरकारी डिफेंस कंपनी बीईएल के शेयर आज सबसे ज्यादा बढ़त के साथ बंद हुए। जबकिटीसीएस के शेयर आज सबसे ज्यादा टूटे।



सेंसेक्स के अन्य शेयरों में आज टाइटन, इंडिगो 2, बजाज फाइनेंस, आईटीसी , अडाणी पोर्ट्स तेजी के साथ बंद हुए जबकि आईसीआईसीआई बैंक और भारती एयरटेल के शेयरों में बदलाव नहीं आया। वहीं इससे पहले आज सुबह बाजार की धीमी शुरुआत हुई। सेंसेक्स 65 अंक टूटकर 76,853.11 के स्तर पर लगभग सपाट स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी 50 भी 0.28 फीसदी की गिरावट के साथ 23742.25 के स्तर पर शुरु हुआ।

पीएनबी और केनरा बैंक ने बदली एफडी ब्याज दरें

- वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा विशेष लाभ

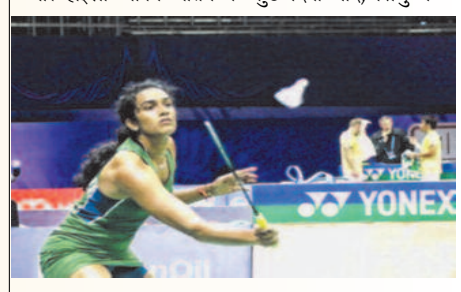
नई दिल्ली ।

यदि आप सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है।

देश के प्रमुख सरकारी बैंकों, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और केनरा बैंक ने हाल ही में अपनी एफडी ब्याज दरों में बदलाव की घोषणा की है, जिससे ग्राहकों को आकर्षक रिटर्न मिलने की उम्मीद है। केनरा बैंक ने 2 नवंबर से अपनी एफडी दरों में 15 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की है। बैंक की 555 दिन की स्पेशल एफडी पर आम ग्राहकों को अब 6.75 फीसदी और वरिष्ठ नागरिकों को 7.25 फीसदी ब्याज मिलेगा। वहीं, 444 दिन की एफडी पर आम ग्राहकों को 6.65 फीसदी और वरिष्ठ नागरिकों को 7.15 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है। तुलनात्मक रूप से, केनरा बैंक की दरें अधिक लुभावनी हैं। दूसरी ओर, पीएनबी ने 1 नवंबर से नई दरें लागू की हैं। बैंक की 444 दिन की स्पेशल एफडी पर आम ग्राहकों को अधिकतम 6.60 फीसदी और वरिष्ठ नागरिकों को 7.10 फीसदी ब्याज मिलेगा। 666 दिन की एफडी पर आम ग्राहकों के लिए 6.50 फीसदी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.00 फीसदी की दर निर्धारित की गई है। ये दरें 3 करोड़ रुपए से कम की घरेलू टर्म डिपॉजिट पर लागू हैं। स्पष्ट है कि वरिष्ठ नागरिकों को दोनों बैंकों में एफडी पर अतिरिक्त लाभ मिलेगा, जिससे उनके लिए यह निवेश और भी आकर्षक हो जाता है।

'मैं अब युवा नहीं रही, बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल के लिया ब्रेक': पीवी सिंधु

नई दिल्ली, एजेंसी। ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। सिंधु इस टूर्नामेंट के लिए ही ब्रेक लिया था। जापान ओपन सुपर 750 और जर्मनी में हाइलो ओपन में जीत हासिल करने के बाद पीवी सिंधु का आत्मविश्वास बढ़ा है। 2022 के बाद यह पहला सीजन है जिसमें सिंधु ने कई बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर टाइटल जीते हैं। पूर्व वर्ल्ड चैंपियन ने सारब्रुकेन में टूर्नामेंट से पहले फ्रेंच ओपन का फाइनल भी खेला था, लेकिन वह दुनिया की नंबर 1 और पेरिस 2024 चैंपियन कोरिया की एन से-यंग से हार गई थीं। हाइलो ओपन जीतने के कुछ दिनों बाद, सिंधु ने



कोरिया ओपन और जापान मास्टर्स छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि उनका शुरुआती प्लान सभी टूर्नामेंट खेलने का था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने शरीर की सुनने और दिसंबर में होने वाले बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल के लिए आराम करने और फिट होने का फैसला किया। बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित मीडिया बातचीत के दौरानएक सवाल पर सिंधु ने कहा, 'लंबा टूर खेलने के बाद, मैंने सोचा था कि मैं कोरिया ओपन और उसके बाद के टूर्नामेंट नहीं खेल पाऊंगी, लेकिन मेरे लिए वापस आकर आराम करना भी जरूरी था। मेरे लिए अपने शरीर का ध्यान रखना और अगले टूर्नामेंट के लिए फिट होना जरूरी था। यही प्लान था। मुझे लगता है कि मेरे लिए यह फैसला लेना जरूरी था कि मैं नहीं खेलूंगी। मुझे अपने शरीर का ध्यान रखना है और कोर्ट पर फिर से मजबूती से वापस आना है। ' सिंधु ने कहा, 'मैं अब जवान नहीं रही, लेकिन मैंने यह भी कहा कि 31 अब नया 21 है, इसलिए मुझे अपने शरीर का ध्यान रखना है। '

नया 3म15 स्कोरिंग सिस्टम 4 जनवरी, 2027 से लागू होगा। सिंधु ने यह भी बताया कि क्या यह गेम को बदल देगा और क्या उनका गेम नए पॉइंट सिस्टम के हिसाब से सही होगा। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को शुरू से ही चौकन्ना रहने और आसान पॉइंट न गंवाने के लिए अलर्ट रहने की जरूरत है। सिंधु ने कहा, '15 पॉइंट्स ऐसी चीज है जिस पर हर किसी को जरूर काम करना चाहिए, और हम इतने सालों से 21 पॉइंट्स पर खेल रहे हैं। इसलिए, हमने यह पक्का किया कि हम उस स्कोरिंग के लिए भी ट्रेनिंग और अभ्यास करें। हर किसी के लिए यह अलग होगा, इसलिए शुरू से ही अलर्ट रहना भी जरूरी है। ' उन्होंने आगे कहा, 'यह जरूरी है कि आप शुरू से ही अलर्ट रहें। यह भी जरूरी है कि जब तक आपको पता चले कि आधा गेम खत्म हो गया है, तब तक आप कोई और आसान पॉइंट न दे सकें।

सेवा क्षेत्र में जोरदार बढ़ोतरी, 4 माह का उच्चतम स्तर

अक्टूबर में एचएसबीसी पीएमआई 55.2 से बढ़कर 55.8 पर पहुंचा

नई दिल्ली ।

भारत के सेवा क्षेत्र ने अक्टूबर में चार महीने की सबसे तेज वृद्धि दर्ज की, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बल मिला है। एचएसबीसी इंडिया सेवा पीएमआई सूचकांक सितंबर के 55.2 से बढ़कर 55.8 पर पहुंच गया, जो मांग में मजबूती और नए ऑर्डर की बंपर आवक को दर्शाता है। अच्छी खबर यह भी है कि लागत का दबाव कम हुआ है, जिससे कंपनियों और उपभोक्ताओं को राहत मिली है। सर्वेक्षण के अनुसार, 50 से ऊपर का अंक विस्तार का सूचक होता है। कंपनियों ने नए ग्राहकों, अनुकूल मांग परिस्थितियों और सफल विज्ञापन अभियानों के दम पर नए ऑर्डर में जोरदार वृद्धि दर्ज की। एचएसबीसी की एक अर्थशास्त्री ने पुष्टि की कि कुल मांग काफी मजबूत बनी रही, जिससे कारोबारी स्थितियों में सतर्कता के साथ सुधार हुआ। हालांकि, कुछ मोर्चों पर सतर्कता भी दिखी। कंपनियों ने भविष्य की संभावनाओं को लेकर आशावादी रहने के बावजूद चार महीने में सबसे कम कर्मचारियों की भर्ती की, जो रोजगार वृद्धि की धीमी रफ्तार को दर्शाता है। नए निर्यात ऑर्डर की वृद्धि लगभग चार साल में सबसे कमजोर रही। अच्छी बात यह है कि कच्चे माल और तैयार उत्पादों की कीमतों में वृद्धि की रफ्तार धीमी हुई, जिससे महंगाई के दबाव में कुछ राहत मिली।

भारत में 2027 से विमान ईंधन में एसएएफ का उपयोग अनिवार्य होगा

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी की ड्राफ्ट एसएएफ पॉलिसी, 2026

नई दिल्ली ।

भारत सरकार हवाई यात्रा को पर्यावरणीय रूप से अधिक टिकाऊ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट एसएएफ पॉलिसी, 2026 के तहत विमानों के ईंधन एटीएफ(एविएशन टर्बाइन फ्यूल) में एसएएफ (सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल) का मिश्रण अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है। इस नई नीति के लागू होने पर, जनवरी 2027 से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में कम से कम एक फीसदी का उपयोग करना होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य हवाई यात्रा से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित यह नीति अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए जनवरी 2027 से एक फीसदी एसएएफ के उपयोग को अनिवार्य करेगी और 2040 तक इस लक्ष्य को 20 फीसदी तक बढ़ाने का स्पष्ट रोडमैप प्रदान करती है। एसएएफ पारंपरिक विमान ईंधन का एक पर्यावरण-अनुकूल विकल्प है, जिसे फसल, जैविक कचरे और अन्य टिकाऊ स्रोतों से तैयार किया जाता है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य हवाई यात्रा के कार्बन पदचिह्न को कम करना है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि एसएएफ गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर खरा उतरे। ड्राफ्ट नीति में केवल एसएएफ मिश्रण के लक्ष्य ही नहीं, बल्कि इनके सख्त अनुपालन पर भी जोर दिया गया है। निर्धारित ब्लेंडिंग जरूरत को पूरा न करने वाली एयरलाइंस और तेल मार्केटिंग कंपनियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, नीति में यह भी प्रस्तावित है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस अपनी वार्षिक एटीएफ जरूरतों का कम से कम 90 फीसदी भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से पूरा करेंगी, जिसका लक्ष्य इकोनॉमिक टैंकरिंग को रोकना है। हवाई अड्डों को एसएएफ के भंडारण, रखरखाव और वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि एसएएफ के उपयोग से एयरलाइंस की ईंधन लागत पर असर पड़ सकता है, खासकर यदि एसएएफ पारंपरिक एटीएफ से महंगा होता है, तो हवाई टिकटों की कीमतों में वृद्धि संभव है। हालांकि, फिलहाल हवाई टिकटों के महंगा होने की कोई तत्काल संभावना नहीं जताई गई है। यह कदम भारत को वैश्विक स्तर पर पर्यावरण अनुकूल हवाई यात्रा को बढ़ावा देने वाले देशों की श्रेणी में खड़ा करेगा।



भारत ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड को पांच विकेट से हराया

कोहली की धमाकेदार बल्लेबाजी; अर्शदीप की घातक गेंदबाजी

ऑकलैंड, एजेंसी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला गया। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। न्यूजीलैंड की पारी 185 रन पर सिमट गई। हालांकि, टारगेट रिवाइज किया गया और भारत को 32 ओवर में 143 रन बनाने थे। भारत ने यह लक्ष्य 22.5 ओवर में पांच विकेट गंवाकर हासिल कर लिया।

भारत पांच विकेट से जीता

भारत ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड को पांच विकेट से हरा दिया है। भारत को डकवर्थ लुईस नियम के तहत जीत के लिए 32 ओवर में 143 रन का लक्ष्य मिला था। टीम इंडिया ने यह लक्ष्य 22.4 ओवर में हासिल कर लिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने पांच मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अगला वनडे सात नवंबर को वेलिंगटन में खेला जाएगा।

न्यूजीलैंड की पारी 185 रन पर सिमटी थी - टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की पारी 40.2 ओवर में 185 रन पर सिमट गई।



स्कोर और भी कम होता, लेकिन आखिरी में ब्लेयर टिकनर की तूफानी पारी ने कीवियों को 180 के पार पहुंचाया। भारत को न्यूजीलैंड के शीर्षक्रम और मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने इतना परेशान नहीं किया, जितना परेशन 11वें नंबर पर आए ब्लेयर टिकनर ने किया। न्यूजीलैंड का स्कोर एक वक्त नौ विकेट पर 146 रन था। इसके बाद टिकनर ने जैकब डफी के साथ 10वें विकेट के लिए 31 गेंद में 39 रन की साझेदारी निभाई। टिकनर 23 गेंद में एक चौका और चार छक्के की मदद से 34 रन की तूफानी पारी खेलकर आखिरी विकेट के रूप में आउट हुए। उन्हें गुरनूर बराड़ ने विकेटकीपर राहुल के हाथों कैच कराया। डफी 15 रन बनाकर नाबाद रहे।

इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी बेहद खराब रही। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ पांच बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा पार कर सके। टिम साइफर्ट 43 गेंद में तीन चौके और दो छक्के की मदद से 38 रन, डेरिल मिचेल 41 गेंद में तीन चौके और एक छक्के की मदद से 28 रन और ग्लेन फिलिप्स 51 गेंद में दो चौके और एक छक्के की मदद से 30 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा टिकनर और डफी ही दहाई का आंकड़ा पार कर सके। विल यंग नौ रन, हेनरी निकोल्स नौ रन, टॉम लाथम तीन रन, कप्तान मिचेल सैंटनर चार रन, नाथन स्मिथ एक रन और काइल जेमीसन एक रन बनाकर आउट हुए। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने चार विकेट लिए, जबकि गुरनूर बराड़ को तीन विकेट मिले। अंशुल कंबोज को दो विकेट मिले।

भारत ने 22.4 ओवर में हासिल किया लक्ष्य - जवाब में भारत की शुरुआत भी खराब रही। रोहित शर्मा खाता खोले बिना आउट हो गए। फिर शुभमन गिल और विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी की। इस बीच मैच को दो बार बारिश के कारण रोकना पड़ा। पहली बार 10.5 ओवर के बाद मैच रोका गया। हालांकि, बारिश रुकी और मैच 40 ओवर का कर दिया गया। संशोधित लक्ष्य 167 रन का किया गया। हालांकि, कुछ गेंदों के बाद फिर बारिश शुरू हो गई और मैच रोकना पड़ा। बारिश जब रुकी तो एक बार फिर लक्ष्य को संशोधित किया गया।

आईपीएल 2027:

13 करोड़ के सनराइजर्स के इस ऑलराउंडर को शामिल करने की तैयारी में चेन्नई?

चेन्नई, एजेंसी। आईपीएल 2027 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की नजर सनराइजर्स हैदराबाद के 13 करोड़ रुपये के खिलाड़ी लियाम लिविंगस्टोन पर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक अन्य फ्रेंचाइजी ने भी दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन सनराइजर्स ने अभी फैसला नहीं लिया है। दूसरी ओर, हार्दिक पांड्या की ट्रेड रेस में पंजाब किंग्स आगे बताई जा रही है। आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन से पहले खिलाड़ियों की ट्रेडिंग को लेकर हलचल तेज हो गई है। हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस छोड़ने की चर्चाओं के बीच अब चेन्नई सुपर किंग्स की नजर सनराइजर्स हैदराबाद के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन पर है। रिपोर्ट के मुताबिक, चेन्नई की टीम इंग्लैंड के इस खिलाड़ी को अपने साथ जोड़ने के विकल्प तलाश रही है। हालांकि,



सनराइजर्स हैदराबाद ने अभी तक इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, चेन्नई सुपर किंग्स लियाम लिविंगस्टोन को अपनी टीम में शामिल करने की संभावनाएं तलाश रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उत्तर भारत की एक अन्य फ्रेंचाइजी ने भी इस खिलाड़ी में दिलचस्पी दिखाई है। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2026 से पहले हुई नीलामी में लिविंगस्टोन को 13 करोड़ रुपये में खरीदा था। हालांकि, उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। उन्होंने पूरे सीजन में केवल दो मुकाबले खेले और 15 रन बनाए। खराब फॉर्म के कारण उन्हें बाकी सीजन में प्लेइंग-11 और इम्पैक्ट प्लेयर के विकल्प में भी जगह नहीं मिली।

संक्षिप्त समाचार

वेनेजुएला में चुनाव तैयारियों पर जोर, रुबियो को कमान

वेनेजुएला , एजेंसी। अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो ने सोमवार को अपने वेनेजुएला के समकक्ष ओलिवर ब्लैंको से मुलाकात की। ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला में चुनाव तैयारियों में तेजी लाने पर जोर दे रहा है। अगले साल चुनाव संभव हैं। दो सप्ताह पहले ही वेनेजुएला ने 2027 में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए एक योजना पर सहमति दी थी। रुबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन इस प्रक्रिया का बारीकी से पालन करेगा। इसका लक्ष्य एक स्थायी चुनाव प्रणाली स्थापित करना है। यह बैठक ट्रंप प्रशासन और कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज की सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण मुलाकात थी। रोड्रिगेज ने जनवरी में अमेरिकी सैन्य अभियान में निकोलस मादुरो को हटाए जाने के बाद पद संभाला था। मादुरो पर मादक पदार्थ तस्करी के आरोप हैं, जिन्हें वह नकारते हैं।

नकाबपोश हमलावरों ने किसान पर जानलेवा हमला किया, पांच गिरफ्तार

डरबन, एजेंसी। दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी प्रांत में हिंसक डकैती के संबंध में पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में 50 वर्षीय किसान डोनावान मार्क्स को गोली मारी गई और उनके कान काट दिए गए थे। ये संदिग्ध 26 से 56 वर्ष के हैं और मंगलवार को आरोपियों को वेंटर्सडॉर्प मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया जाएगा। उन पर घर में डकैती, हत्या का प्रयास और अवैध हथियार व गोला-बारूद रखने के आरोप हैं। पुलिस ने पहले दो, फिर रविवार को तीन और संदिग्धों को पोटचेफस्ट्रूम के पास पकड़ा। अधिकारियों ने चार हथियार, कपड़े व आभूषण जब्त किए। हमला 28 अक्तूबर को साइफरफोंटेन के एक खेत पर हुआ। तीन नकाबपोश हमलावरों ने किसान को गोली मारी, चाकू से हमला किया, तीन हथियार चुराए और उसके पिकअप वाहन में भाग गए। किसान अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हुआ था और अब ठीक हो रहा है। मोरल रीजेनरेशन मूवमेंट ने कहा कि किसानों पर हमले खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी स्टडीज के शोध से पता चला है कि डकैती मुख्य मकसद है, न कि श्वेत किसानों के खिलाफ 'श्वेत नरसंहार' जैसा कोई संगठित अभियान।

वोटिंग से कुछ घंटे पहले अमेरिका का ईरान पर हमला :केश्म द्वीप पर 5 धमाके



तेहरान, एजेंसी। अमेरिका में मंगलवार को मिडटर्म चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इससे पहले सोमवार को ईरान के केश्म द्वीप पर कम से कम पांच जोरदार धमाके हुए। कुछ दूर पर बंदर लेंगेह शहर में भी विस्फोट की खबर है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि यह हमला अमेरिका ने किया है। हालांकि, ईरानी मीडिया ने इसके पीछे अमेरिका या इजराइल का हाथ होने की पुष्टि नहीं की है। उसने अमेरिका के दो एमक्यूएम-170 जासूसी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। केश्म द्वीप करीब 1,445 वर्ग किलोमीटर में फैला, ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है। यह कभी फ्री-ट्रेड जोन और टूरिस्ट स्पॉट के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यह एक बड़े सैन्य ठिकाने में बदल चुका है। होर्मुज स्ट्रेट के प्रवेश द्वार पर मौजूद यह द्वीप रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। अमेरिका इसे कई वजहों से बड़ा सैन्य खतरा मानता है। अंडरग्राउंड सैन्य नेटवर्क: रिपोर्ट्स के मुताबिक, केश्म द्वीप के नीचे सुरंगों और नमक की गुफाओं का बड़ा नेटवर्क है। यहां ईरान ने तटीय मिसाइल सिस्टम और तेज हमला करने वाली नौकाएं छिपाकर रखी हैं। समुद्री रास्तों पर नियंत्रण के लिए अहम: द्वीप के अंदर ईरान ने ऐसे सैन्य ठिकाने बनाए हैं, जिनका मकसद समुद्री रास्तों पर नियंत्रण रखना है। माना जाता है कि यहां से होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही रोकी या सीमित की जा सकती है।

पीएम मोदी को खड़गे की चुनौती, राहुल गांधी से खुली बहस क्यों नहीं कर रहे?

राहुल गांधी ने कहा, 24 घंटे हो गए अभी तक जबाव नहीं आया

नई दिल्ली , एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधकर सवाल किया है कि वे वोट चोरी के आरोपों का जवाब देने से क्यों बच रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को खुली बहस की चुनौती दी है, लेकिन अब तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गंभीर सवालों का सामना करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के खिलाफ दिमागी नक्सल जैसे बयान दे रहे हैं। कांग्रेस नेता खड़गे ने पोस्ट कर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की घेराबंदी की। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता खड़गे का आरोप है कि आयोग ने इस प्रक्रिया को लेकर पांच बार अपना रुख बदला है। उन्होंने फॉर्म-6 का जिक्र कर दावा किया कि चुनाव आयोग के कुछ अन्य आयुक्तों ने इस फार्म को गैरकानूनी बताया था।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री देश में तीन करोड़ घुसपैठियों के होने का दावा करते हैं, लेकिन इतने वर्षों तक इस पद पर रहने के बावजूद अवैध घुसपैठ रोकने में मोदी सरकार क्यों सफल नहीं हुई? खड़गे ने मामले में केंद्रीय गृह मंत्री की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए।

कांग्रेस नेता खड़गे ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की मांग और वोट बचाओ रैली का उल्लेख कर कहा कि इन घटनाओं से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को परेशान कर दिया हैं। उन्होंने संसद सत्र को लेकर भी मोदी सरकार पर सवाल उठाए। खड़गे के मुताबिक, बीते संसद सत्र के समाप्त होने के 83 दिन बाद सरकार विशेष सत्र बुलाने की बात कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से संसद में आकर पत्रकारों के सामने सवालों का जवाब देने और राहुल गांधी के साथ खुली बहस करने की मांग की। इसके पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को खुली बहस की चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि उनकी चुनौती के 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी पसंद का मंच और स्थान चुन सकते हैं। बहस के दौरान मीडिया और देश के युवाओं की मौजूदगी भी होनी चाहिए। उन्होंने बहस का मुद्दा देश विरोधी गतिविधियों और विदेशी ताकतों से संबंधों को बनाने की बात कही। राहुल गांधी ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत बहस के निर्णायक हो सकते हैं।

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर विदेशी ताकतों की मदद से



सत्ता में आने और उनके सहारे सत्ता में बने रहने के आरोप लगाए थे। उन्होंने भारत की वित्तीय व्यवस्था पर भी विदेशी ताकतों के प्रभाव का दावा किया था। यह राजनीतिक विवाद गुजरात में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम के बाद तेज हुआ। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर देश के विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया था। इसके बाद से कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।

श्रीनगर में आग से 80 अस्थायी शेल्टर राख, कबाड़ा जमा करने वाले दो लोगों की मौत

श्रीनगर, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में आग लगने से दो कबाड़ इकट्ठा करने वालों की मौत हो गई और करीब 80 अस्थायी शेल्टर जलकर राख हो गए। अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर के बेमिना के दुर्बल में सुबह-सुबह अस्थायी शेल्टर में लगी भीषण आग में दो कबाड़ इकट्ठा करने वालों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि आग आधी रात को लगी, जिसने तिरपाल और लकड़ी से बने करीब 80 अस्थायी शेल्टरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग में एक खाली पोल्ट्री फार्म और एक टिपर को भी नुकसान पहुंचा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया।



चश्मदीदों ने बताया कि आग बुझाने के लिए फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाने से पहले ही आग पूरे इलाके में फैल चुकी थी। आग पर काबू पाने के बाद मलबे से दो लाशें मिलीं। मरने वाले दोनों लोग दिल्ली के रहने वाले थे। उनकी पहचान मोहम्मद नूर आलम (27) और अल अमीन (16) के रुप में हुई। दोनों बेमिना के दुर्बल में स्क्रैप इकट्ठा करने का काम करते थे। अधिकारियों ने कहा कि एफएसएल की कार्रवाई पूरी होने के बाद दोनों शव पुलिस को सौंप दिए गए। आग लगने की वजह का पता नहीं चला है। पुलिस ने इस घटना में केस दर्ज कर लिया है। अधिकारियों ने कहा है कि करीब 80 से 95 फीसदी आग लगने की वजह इंसानी गतिविधियां होती हैं। बिना देखरेख के या ठीक से न बुझाए गए कैंपफायर आग लगने का एक मुख्य कारण हैं। गाड़ियों से या चलते समय लापरवाही से फेंके गए सिगरेट के टुकड़े, यार्ड का कचरा, कूड़ा या खेती/काट-छांट कर जलाए गए खेत जो काबू से बाहर हो जाते हैं, चेनसॉ, गाड़ियों, या सूखी सड़कों पर टो चेन खींचने से निकलने वाली चिंगारी, और गिरी हुई बिजली की लाइनें, ये सभी अचानक आग लगने के बड़े कारण हैं।

अपनी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड लेकर चलना मजबूरी है, मरवा सकते हैं खान सर

- ज्ञान बिंदु कोचिंग के मालिक रौशन आनंद ने एक इंटरव्यू में लगाए गंभीर आरोप

पटना, एजेंसी। बिहार में खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के मालिक रौशन आनंद के बीच विवाद फिर चर्चा में है। रौशन आनंद ने एक इंटरव्यू में खान सर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड लेकर चलना उनकी मजबूरी है। रौशन आनंद ने दावा किया कि खान सर उन्हें भी मरवा सकते हैं और अपने बचाव के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि खान सर बेहद धूर्त हैं और यदि उन्हें लगता है कि किसी की जान लेकर वह सुरक्षित रह सकते हैं, तो वह ऐसा भी कर सकते हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आनंद ने 2 जून को हुई गोलीबारी की घटना को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होने पर सच्चाई सामने आ जाएगी। उनके मुताबिक गोलीकांड सरकारी बॉडीगार्ड हासिल करने के उद्देश्य से किया गया था। उन्होंने खुद पर दर्ज प्राथमिकी को झूठा बताते हुए कहा कि 3 जून की सुबह करीब 4 बजे बिना उचित जांच के उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। आनंद ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए खान सर के खिलाफ लगाए गए पुराने आरोपों की जांच नहीं होने का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने मोकामा के विधायक अनंत सिंह के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि ना जीने की खुशी, ना मरने का गम। रौशन आनंद ने कहा कि अब उनकी जिंदगी भी इसी स्थिति में पहुंच गई है। उन्होंने अपने भाई प्रिंस की नेपाल में संदिग्ध मौत का जिक्र करते हुए खान सर पर गंभीर आरोप भी लगाए। हालांकि, खान सर इन आरोपों को पहले ही बेबुनियाद बता चुके हैं।

अब्दुल रहमान की जीत पर ओवैसी... अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएंगे

मिशीगन से सीनेट चुनाव जीतकर रखा इतिहास

नई दिल्ली, एजेंसी । अमेरिका के मिशिगन में अब्दुलर हमान मोहम्मद अल-सैयद की सीनेट चुनाव में जीत ने दुनियाभर में सुर्खियां बटोरी हैं। वह अमेरिकी सीनेट के लिए चुने जाने वाले पहले मुस्लिम हैं, जिसकी गूंज भारत तक पहुंची और एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जीत को उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए राजनीतिक पहचान मजबूत करने का संदेश बताया।

ओवैसी ने लिखा, एक अब्दुल मिशिगन में जीत गया, अब यूपी के अब्दुल को भी अपनी सियासी पहचान मज़बूत करनी होगी। संघियों ने अब्दुल को तंज़ में बदलने की बहुत कोशिश की है। वक़्त आ गया है कि हम दिखाएं कि अब्दुल अल्लाह के सिवा किसी की गुलामी नहीं करता। अब दरी नहीं



बिछाएंगे। उनका यह बयान उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपनी राजनीतिक ताकत पहचानने और मजबूत करने की अपील के तौर पर देखा जा रहा है।

बात दें कि मिस्र-अमेरिकी मूल के डॉक्टर और प्रगतिशील नेता अल-सैयद ने मिशिगन में रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स के खिलाफ एक कड़े मुकाबले में जीत हासिल की। उनकी यह जीत अमेरिकी राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण मानी जा रही है, खासकर इसलिए क्योंकि उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान लगातार इस्लामोफोबिक हमलों का सामना करना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें जिहादी तक कहा और यहां तक कि अपनी ही पार्टी के भीतर से भी उन्हें विरोध झेलना पड़ा, जब अगस्त में उनसे प्राइमरी में हारने वाली हेली स्टीवंस ने रिपब्लिकन उम्मीदवार का समर्थन कर दिया।

जीत का दावा करने के बाद, अल-सैयद ने अपने भाषण में अमेरिकी व्यवस्था पर कॉरपोरेट कंपनियों और अरबपतियों के बढ़ते प्रभाव पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर देश में लोगों को राशन, पेट्रोल, घर या डॉक्टर को दिखाने जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। अल-सैयद ने स्पष्ट किया कि करदाताओं का पैसा लोगों और उनके बच्चों पर खर्च होना चाहिए, न कि दूसरे देशों के बच्चों पर बम गिराने में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका की महानता अपनी कमियों को नजरअंदाज करने में नहीं, बल्कि उन्हें सुधारने की हिम्मत दिखाने में है। उनकी यह जीत अमेरिकी राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है।

अगर डेमोक्रेट्स जीते तो मैं बन जाऊंगा 'मिस्टर वीटो' : ट्रंप

वाशिंगटन , एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर मध्यावधि चुनावों (मिडटर्म इलेक्शन) में डेमोक्रेट्स कांग्रेस पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं, तो वह भविष्य में उनकी ओर से लाए गए किसी भी कानून को वीटो (अधिकार का इस्तेमाल कर रोकना) कर देंगे। सोमवार को जारी 'न्यूयॉर्क पोस्ट' के पॉडकास्ट 'पॉड फोर्स वन' में मिरांडा डिवाइन को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, 'मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अगर हम नहीं जीते, तो मैं हर चीज को वीटो कर दूंगा। मैं बस वीटो ही करता रहूंगा।' रविवार को प्रसारित एक प्रीव्यू क्लिप में ट्रंप ने कहा, 'मुझे लगता है कि मैं 'मिस्टर वीटो' बन जाऊंगा।' उन्होंने कहा कि एक-दो महीने तक लगातार वीटो करने के बाद, डेमोक्रेट्स 'खुद चलकर आएंगे और



एक समझौता करेंगे। तीसरे कार्यकाल के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, 'अगर मुझे मौका मिलता, तो मैं फिर से चुनाव लड़ना पसंद करता, लेकिन संविधान की भाषा बहुत सख्त है। मैं जरूर लड़ना चाहता। हाल ही में एक पोल हुआ था जिसमें मैं बाकी सभी से काफी आगे था। मैं चुनाव लड़ना पसंद करता, लेकिन कोई बात नहीं।' अमेरिकी संविधान का 22वां संशोधन कहता है कि कोई भी व्यक्ति दो बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता। 80 वर्षीय ट्रंप ने 2016 और 2024 में राष्ट्रपति पद जीता था। उन्होंने कहा, 'हमारे पास अभी दो साल से ज्यादा का समय बचा है। यह काफी लंबा समय होता है। इतने समय में बहुत कुछ किया जा सकता है, और आपने देखा ही है कि हमने अब तक क्या काम किया है।

ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर डेमोक्रेट्स कांग्रेस जीतने के बाद उनके लिए काम करने वाले लोगों के खिलाफ जांच शुरू करते हैं, तो वह उन लोगों को पहले से ही 'माफी' (पार्डन) देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, 'अगर जरूरत पड़ी, तो मैं बिल्कुल ऐसा करूंगा... मुझे इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बस कर दूंगा। मैंने जे6 (6 जनवरी की घटना) के मामले में भी ऐसा ही किया था। उन्होंने उन पोल (सर्वे) को खारिज कर दिया जिनमें डेमोक्रेट्स को आगे दिखाया गया है। ट्रंप ने कहा, 'मुझे लगता है कि इन पोल्स में धांधली हुई है। मुझे तो लगता है कि कई पोल करने वाली एजेंसियां तो लोगों को सर्वे के लिए बाहर भेजती ही नहीं हैं। हो सकता है कि वे रिपब्लिकनों के बीच पोल न करते हों, लेकिन मुझे लगता है कि हम काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मैं रैलियों के आधार पर ऐसा कह रहा हूं।' ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर डेमोक्रेट्स हाउस, सीनेट और बाद में व्हाइट हाउस जीत जाते हैं, तो 'हमारा देश खत्म हो जाएगा। ज्यादातर पब्लिक पोल में हाउस जीतने के मामले में डेमोक्रेट्स का पलड़ा भारी दिख रहा है। रविवार को जारी न्यू यॉर्क टाइम्स/सिएना के अंतिम पोल के अनुसार, कंसास, ओहियो, मेन, टेक्सास और मिशिगन में डेमोक्रेटिक सीनेट उम्मीदवार 5 से 11 अंकों से आगे चल रहे हैं।

मेक्सिको: स्कूलों में बच्चे नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे फोन, सरकार ने लगाया प्रतिबंध

मेक्सिको सिटी , एजेंसी। मेक्सिको में अब स्कूलों में पढ़ाई के दौरान मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लागू होने जा रहा है। सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद बच्चों और किशोरों को मोबाइल की लत, तनाव और पढ़ाई के दौरान ध्यान भटकने जैसी समस्याओं से बचाना है। हालांकि, देश के कई हिस्सों में माता-पिता इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी चिंता बच्चों की सुरक्षा को लेकर है। मेक्सिको के कई इलाकों में संगठित अपराध और गोलीबारी की घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे में माता-पिता का कहना है कि अगर बच्चों के पास मोबाइल नहीं होगा तो किसी आपात स्थिति में वे उनसे संपर्क कैसे कर पाएंगे। सरकार ने स्कूलों में मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगाई है, लेकिन इस फैसले ने बच्चों की पढ़ाई और उनकी सुरक्षा के बीच बहस छेड़ दी है। यह प्रतिबंध राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम की सरकार की पहल का हिस्सा है। इसके तहत प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पूरे स्कूल समय के दौरान मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, कुछ खास परिस्थितियों में छूट दी गई है। छात्र शिक्षक के निर्देश पर पढ़ाई से जुड़े काम के लिए मोबाइल इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा निजी आपात स्थिति, दिव्यांगता और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों में भी फोन के इस्तेमाल की अनुमति होगी। छात्र स्कूल आने-जाने के दौरान अपने साथ मोबाइल रख सकते हैं। यानी प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य स्कूल के अंदर पढ़ाई



के समय मोबाइल के इस्तेमाल को रोकना है। सरकार का मानना है कि इससे बच्चों का डिजिटल उपकरणों पर निर्भर रहना कम होगा और वे पढ़ाई पर बेहतर ध्यान दे सकेंगे।

सरकार ने मोबाइल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला क्यों किया : मेक्सिको सरकार का कहना है कि बच्चों और किशोरों में डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल से कई तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं। इनमें मोबाइल की लत, ध्यान की कमी, तनाव और बेचैनी जैसी समस्याएं शामिल हैं। देश के शिक्षा मंत्री मारियो डेलगाडो ने प्रतिनिधि सभा में कहा कि राष्ट्रपति शीनबाम की सरकार का उद्देश्य बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म की लत और उससे पैदा होने वाली परेशानियों से बचाना है।

सरकार इसी महीने डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए नए नियम भी लागू करने की तैयारी कर रही है। इन नियमों के तहत प्लेटफॉर्म को नफरत फैलाने वाली पोस्ट, दुर्व्यवहार, यौन हिंसा, उत्पीड़न, साइबर बुलिंग और अन्य गैरकानूनी सामग्री हटानी होगी। सरकार का मानना है कि बच्चों को डिजिटल दुनिया के नुकसान से बचाने के लिए स्कूलों में मोबाइल पर नियंत्रण जरूरी है।

यूके में स्थायी निवास नियम: गृह मंत्रालय के फैसले से भारतीयों को लाभ, केयर वर्कर पर शबाना महमूद का रुख क्या?

लंदन, एजेंसी। ब्रिटेन में स्थायी निवास से जुड़े नियम पर सरकार ने अहम फैसला लिया है। गृह मंत्रालय के नए फैसले से भारतीयों को लाभ होगा। केयर वर्कर से जुड़े इस नियम को लेकर गृह मंत्री शबाना महमूद अपने सख्त रुख से पीछे हटी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार विदेशी केयर वर्कर के लिए स्थायी निवास की प्रतीक्षा अवधि को तीन गुना करने के अपने पहले के सख्त रुख से पीछे हट गई। इस कदम से हेल्थ एंड सोशल केयर वीजा मार्ग का उपयोग करने वाले कई भारतीयों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। एक साल तक चले सार्वजनिक परामर्श के बाद, महमूद ने संसद को बताया कि वह एक 'निष्पक्ष समझौते' पर पहुंची हैं। इसके तहत कोविड महामारी के बाद देश की सेवा करने वाले केयर वर्कर को पांच साल में स्थायी निवास की अनुमति दी जाएगी।

कितने भारतीय लोगों को वीजा विस्तार का लाभ मिला: सोमवार को गृह कार्यालय ने इस साल के नवीनतम आंकड़े जारी किए। इसके अनुसार, दिसंबर 2025 को समाप्त हुए वर्ष में हेल्थ एंड सोशल केयर श्रेणी के तहत 1,04,555 वीजा विस्तार पाने वाले श्रमिकों में भारतीय सबसे आगे हैं। इनमें से अधिकांश अब अपनी अनिश्चितकालीन निवास अनुमति (आईएलआर) के लिए मूल रूप से निर्धारित पांच साल की समय-सीमा के भीतर पात्र



होंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने एक बयान में कहा कि लोग एक ऐसी आव्रजन प्रणाली देखना चाहते हैं जो नियंत्रण, योगदान और नियमों का पालन करने वालों को पुरस्कृत करने पर आधारित हो। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव इसी सिद्धांत पर आधारित हैं और हमारे देश में विदेशी श्रमिकों के योगदान को मान्यता देते हैं। आव्रजन नियमों में क्या बदलाव हुए हैं बर्नहैम ने कहा कि ब्रेग्जिट के बाद पिछली सरकार ने आव्रजन पर नियंत्रण खो दिया था, जिससे संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। उन्होंने गृह सचिव के इस समस्या को संभालने के प्रयासों का पूरा समर्थन किया। उन्होंने दोहराया कि यह 'केवल निष्पक्ष' है कि देश में सबसे मूल्यवान योगदान देने वाले प्रवासियों को जल्दी स्थायी निवास का अवसर दिया जाए। अन्य भूमिकाओं में काम करने वालों को अधिक समय तक इंतजार करना होगा। जो लोग प्रणाली का दुरुपयोग करते हैं या अवैध रूप से आते हैं, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा या उन्हें भी अधिक समय तक इंतजार करना होगा। गृह कार्यालय ने पुष्टि की है कि कोविड-19 महामारी से जूझ रहे ब्रिटेन में केयर वर्कर के योगदान को देखते हुए, जो लोग अपने वीजा की शर्तों को पूरा करते हैं और सालाना कम से कम 25,000 पाउंड कमाते हैं, वे पांच साल के बाद स्थायी निवास कर सकेंगे। भारतीयों को कैसे मिलेगा लाभ और कौन जल्दी स्थायी निवास कर पाएगा? शबाना महमूद के माता-पिता ने कश्मीर से ब्रिटेन प्रवास किया था। उन्होंने अपने परिवार के अनुभव का उल्लेख किया। उन्होंने 'अर्जित स्थायी निवास' प्रवास योजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया। इन योजनाओं में अधिक आय वालों को स्थायी निवास के लिए तेज मार्ग से पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि केयर वर्कर वीजा मार्ग का भी 'दुरुपयोग' किया गया था। बेईमान और शोषणकारी कंपनियां ऐसे श्रमिकों को प्रायोजित कर रही थीं, जिनके लिए वास्तव में कोई नौकरी मौजूद नहीं थी। जो लोग पांच साल के स्थायी निवास के लिए योग्य नहीं हैं, जो कुल संख्या का लगभग एक चौथाई है, उन्हें एक नए पांच साल के वीजा के माध्यम से योगदान करने का दूसरा मौका दिया जाएगा। गृह कार्यालय ने कहा है कि वे इन वीजा को पूरा करने के बाद ही स्थायी निवास के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी तरह का दृष्टिकोण स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में सार्वजनिक सेवा कर्मियों पर भी लागू होगा, जो इसी अवधि के दौरान पहुंचे थे।

नेक्सटऐज मीडिया एंड कंालटिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए, प्रकाशक, संपादक अनीता यादव द्वारा मुद्रक, रजनी कुमारी मेसेर्स साईं प्रिंटिंग प्रेस डी-85 सेक्टर-06 201301 से मुद्रित कराकर 962 सरफाबाद सेक्टर-73, नोएडा-201304 से प्रकाशित किया,
प्रधान संपादक : रिंकू यादव संपादक : अनीता यादव PRGI No. UPHIN/26/A8255 Ph. : 4403949, Email : unplugindia26@gmail.com